TRAI

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

टेलिकॉम लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार पर सिफारिशें

21 फरवरी 2020

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली- 110002

विषय सूची

अध्याय I - परिचय..... 1

अध्याय -II: लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के मौजूदा दिशानिर्देशों का परीक्षण.....3

अध्याय -III: सिफारिशों का सारांश..... 33

अध्याय I – परिचय

A. दूरसंचार विभाग सन्दर्भ

1.1 दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने पत्र क्रमांक 20- 281/2010-AS-I Vol। XII (pt) दिनांक 8 मई 2019 **(अनुलग्नक -1.1),** अन्य बातों के साथ-साथ, के माध्यम से सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP), 2018 को भारत सरकार द्वारा अपने 'प्रोपल इंडिया' मिशन के तहत जारी किया गया है,जिसकी एक रणनीति के रूप में डिजिटल संचार क्षेत्र हेतु निवेश को प्रेरित करने की कल्पना की गई है, और विलय और अधिग्रहण के दिशा-निर्देश,2014 में सुधार करके अनुपालन बाधाओं को सरल और सुविधाजनक बनाना अनुमोदन के सरलीकरण और तेजी से ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए उपर्युक्त रणनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजना में से एक है। उक्त पत्र के माध्यम से दिनांक 8 मई 2019,को DoT ने अन्य बातों के साथ-साथ TRAI से TRAI संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम, 1997(यथा संशोधित) की धारा 11 की उप-धारा (1) की धारा (ए) के शर्तों के अंतर्गत कि 'विलय और अधिग्रहणों के दिशानिर्देश 2014 में सुधार' के लिए सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

1.2 11 जून 2019 **(अनुलग्नक -1.2)** के अपने बाद के पत्र के माध्यम से, DoT ने और निविष्टियां प्रदान किए और अनुरोध किया कि सरलीकरण को सक्षम करने और अनुमोदन के तेजी से ट्रैकिंग हेतु विलय और अधिग्रहण के दिशानिर्देश,2014 में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करते समय इस पर विचार किया जा सकता है। 11 जून 2019 दिनांकित पत्र में, DoT ने सूचना दी कि उसने पिछले पांच वर्षों में लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए कई प्रस्तावों की जांच की है। लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के प्रस्ताव की जांच करने के बाद, DoT मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर लागू शर्तों को पूरा करने के अधीन रिकॉर्ड विषय पर स्थानांतरण / विलय को लेने के लिए अपनी मंजूरी देता है। अतीत में कई उदाहरणों में, संस्थाओं ने माननीय TDSAT के समक्ष DoT द्वारा अन्य बातों के साथ उन पर लगाई गई लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 3 (i) और 3 (m) के कुछ शर्तों को दबाने और रद्द करने की प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की है। माननीय TDSAT ने कई मौकों पर ऐसे कुछ शर्तों के संचालन को रोक दिया है। इसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड में लिए गए विलय में देरी हुई है। इसके अलावा, DoT ने 16 नवंबर 2018 को वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (VNOAI) से प्राप्त प्रतिनिधित्व की एक प्रति अग्रेषित की, जिसमें मोबाइल बिटस्ट्रीम एक्सेस (MBA) आधार

पर MVNOs के लिए थोक क्षमता का 20% अलग सेट करने हेतु विलय की गई इकाई पर एक प्रतिबद्धता लगाने का सुझाव दिया गया है।

B. परामर्श प्रक्रिया

2 हितधारकों की टिप्पणियाँ मांगते हुए 19 सितंबर 2019 को "दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देशों को सुधारना" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। टिप्पणियों और काउंटर टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 1 नवंबर 2019 और 15 नवंबर 2019 थी। प्राधिकरण को 9 हितधारकों से टिप्पणियाँ मिलीं और 2 हितधारकों से काउंटर टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये TRAI की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में मुक्त परिचर्चा 23 दिसंबर 2019 को आयोजित की गयी थी।

3 हितधारकों से प्राप्त इनपुट और उसके आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों में तीन अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय विषय का परिचय देता है। अध्याय- II में मुद्दों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और विश्लेषणों के आधार पर चर्चा की गई है, जिनके आधार पर सिफारिशों को तैयार किया गया है। अध्याय- III सिफारिशों का सारांश प्रदान करता है।

अध्याय- II: लाइसेंसों के स्थानांतरण / विलय के मौजूदा दिशानिर्देशों का परीक्षण

A. पृष्ठभूमि

2.1 विलय और अधिग्रहण (M&A) किसी भी क्षेत्र में स्वाभाविक हैं। M&A के कई लाभ हैं जैसे कि स्केल की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार, दक्षता बढ़ाना, निवेश को आकर्षित करना, संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और सेवाओं की सामर्थ्य बढ़ाना। हालांकि, M&A के परिणामस्वरूप बाजार में बढ़ी हिस्सेदारी एकाधिकार की शक्ति का कारण बन सकती है और जिससे प्रभावी प्रतिस्पर्धा कम होती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें ऊँची होती हैं। आम तौर पर, किसी भी क्षेत्र में, प्रतियोगिता का स्तर प्रतियोगियों की संख्या के साथ जुड़ा होता है यानी जितना अधिक उतना अच्छा होता है। हालांकि, दूरसंचार एक पूंजीगत प्रोत्साहन क्षेत्र है और मोबाइल सेवाओं के प्रावधान में सीमित प्राकृतिक संसाधन का उपयोग शामिल है, यानी स्पेक्ट्रम, जिसकी दक्षता प्रतियोगियों की बढ़ती संख्या के साथ कम हो जाती है क्योंकि यह विखंडन की ओर जाता है, गार्ड बैंड के बढ़े प्रावधान की आवश्यकता होती है। इसलिए, विलय और अधिग्रहण की एक नीति ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है जो M&A गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में कोई समझौता नहीं हो।

2.2 दूरसंचार सेवाओं लाइसेंस/प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के लिए मौजूदा दिशानिर्देश, एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के समामेलन के तहत 20 फरवरी 2014 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए थे जिसे क्रमशः "स्पेक्ट्रम कैप से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 21 नवंबर 2017 और "इज ऑफ़ डूइंग टेलीकॉम बिजनेस" पर दिनांक 30 नवम्बर 2017 के TRAI की प्रतिक्रियाओं के आधार पर दो अवसरों 30 मई 2018 और 24 सितम्बर 2018 को संशोधित किया गया है। हस्तांतरण/ लाइसेंस के विलय पर दिशानिर्देशों (यथा संशोधित) के खंड 3 (14 प्रावधानों वाले) दिनांकित 20 फरवरी 2014 के तहत विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

2.3 हाल के दिनों में, दूरसंचार पहुंच सेवा बाजार समेकन के एक चरण से गुज़री है, तथा लाइसेंस के कई हस्तांतरण / विलय हुए हैं। वर्तमान में, 2010-2011 में 12-14 की तुलना में प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में 4 पहुंच सेवा प्रदाता हैं, जब प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस के विलय पर अंतिम सिफारिशें की गई थीं।

2.4 समय बीतने के साथ, कुछ खंड निरर्थक हो सकते हैं, जबकि कुछ अस्पष्ट हो सकते हैं

और जो स्पष्टता की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP), 2018, 'प्रोपेल इंडिया' मिशन के तहत, अन्य बातों के साथ,डिजिटल संचार क्षेत्र में निवेश उत्प्रेरक के रणनीति के तहत अनुमोदन के सरलीकरण और तेजी से निगरानी को सक्षम करने के लिए विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश,2014 में सुधार,' की परिकल्पना करता है।

2.5 इसके अलावा,11 जून, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि कई विलय प्रस्तावों में, संस्थाओं ने माननीय TDSAT के समक्ष दूरसंचार विभाग द्वारा उनपर लगाए गये लाइसेंस के स्थानांतरण / विलय के दिशानिर्देशों के अन्य बातों के साथ, अनुच्छेद 3 (i) और 3 (m) के कुछ शर्तों को दबाने और अलग करने, के संदर्भ में प्रार्थना की याचिका दायर की है। कई अवसरों पर माननीय TDSAT ने ऐसी कुछ शर्तों के संचालन को रोक दिया है। इसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड में लिए जा रहे विलय में अनावश्यक देरी हुई है।

2.6 उपरोक्त के मद्देनजर, हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अनुमोदन के सरलीकरण और तेजी से निगरानी को सक्षम करने के लिए लाइसेंस के स्थानांतरण / विलय के मौजूदा दिशानिर्देशों में किए जाने वाले सुधारों पर अपने इनपुट प्रदान करें। हितधारकों से विस्तृत तर्कसंगतता के साथ खंड-वार प्रतिक्रिया प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। अगला भाग हितधारकों और उनके परीक्षण/ विश्लेषण से प्राप्त खंड-वार प्रतिक्रियाएँ प्रदान करता है।

B. लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों की जांच

a. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(a)

2.7 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (a) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"ट्रिब्यूनल या कंपनी के न्यायाधीश के समक्ष दायर कंपनियों के समझौते, व्यवस्था और समामेलन के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए लाइसेंसकर्ता को सूचित किया जाएगा। आगे, लाइसेंस के विलय / हस्तांतरण पर ऐसी योजना पर लाइसेंसकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व / आपत्ति, यदि कोई हो तो एकीकृत लाइसेंस के तहत प्राधिकरण को इस तरह के नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी संबंधितों को बनाना और सूचित करना होता है। ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश द्वारा योजना को स्वीकृति दिए जाने के बाद, लाइसेंसकर्ता एकीकृत लाइसेंस के तहत लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण / विलय के मंजूरी का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसकी लिखित स्वीकृति प्रदान करेगा।"*

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.8 कुछ हितधारकों ने कहा है कि चूंकि दूरसंचार विभाग पहले से ही NCLT विलय की

कार्यवाही का एक हिस्सा है, इसलिए विलय संस्थाओं को अपनी मंजूरी के लिए दूरसंचार विभाग से अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और दूरसंचार विभाग की स्वीकृति NCLT विलय / डिमर्जर प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए, हितधारकों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अनुसार, आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनियों को केंद्र सरकार, आईटी प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, SEBI, रजिस्ट्रार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, आधिकारिक परिसमापक, CCI, यदि लागू हो, और दूरसंचार विभाग सहित अन्य सेक्टोरल विनियामक या प्राधिकरण जिनकी योजना से प्रभावित होने की संभावना है, इस योजना को दाखिल करने की आवश्यकता है ।सूचीबद्ध आवश्यकताओं और सूचीबद्ध अधिनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सभी अनुमोदन NCLT द्वारा योजना को मंजूरी देने से पहले हैं और योजना में शामिल आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनियों को NCLT द्वारा मंजूरी के बाद किसी भी प्राधिकरण से फिर से मिलने की आवश्यकता नहीं है।। NCLT प्रक्रिया के दौरान ही अन्य सभी प्राधिकरणों से प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, से निपटा जाता है। दूरसंचार विभाग NCLT प्रक्रिया का एक हिस्सा है और पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनियों को अभी भी रिकॉर्ड पर लाइसेंस या दूरसंचार व्यवसाय के डीमर्जर / विलय की मंजूरी के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क करना होगा।

- NCLT की कार्यवाही में कम से कम 8-12 महीने लगते हैं, और दूरसंचार विभाग से अनुमोदन में 2-4 महीने जिससे डीमर्जर / विलय को पूरा होने के लिए 10-16 महीने की कुल समय सीमा हो जाती हैं। इससे विलय संस्थाओं को समय और मूल्य का बड़ा नुकसान होता है।

2.9 एक हितधारक ने प्रस्तुत किया है कि दूरसंचार विभाग को विलय रिकॉर्ड करने के लिए प्रदान की गई 30 दिनों की समयावधि को अनिवार्य किया जाना चाहिए; यदि दिए गए समय-सीमा के भीतर इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विलय को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए।

विश्लेषण

2.10 2017 में "ईज ऑफ डूइंग टेलीकॉम बिजनेस" की सिफारिशों पर जोर देते हुए, हितधारकों ने इस मुद्दे को उठाया था और अनुरोध किया था कि एक बार NCLT द्वारा विलय को मंजूरी देने के बाद, एक परिभाषित समयरेखा होनी चाहिए, जिसके भीतर, दूरसंचार

विभाग को लाइसेंस के विलय को अपनी लिखित स्वीकृति देनी चाहिए। 2014 के M&A दिशानिर्देशों के खंड 3 (a) के अनुसार, ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर कंपनियों के समझौते, व्यवस्था और समामेलन के किसी भी प्रस्ताव के लिए लाइसेंसकर्ता को सूचित किया जाना आवश्यक है। इस योजना पर लाइसेंसधारक द्वारा आगे, प्रतिनिधित्व / आपत्ति, यदि कोई हो, तो इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी संबंधितों को बनाया और सूचित किया जाना चाहिए। इस विचार के साथ कि एक बार विलय की योजना को NCLT द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें दूरसंचार विभाग की आपत्तियों (यदि कोई है) पर पहले ही विचार किया जा चुका है, तो लाइसेंसकर्ता को कम समय में ही,लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय / हस्तांतरण के लिए अपनी लिखित स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में होना चाहिए। प्राधिकरण ने निम्नलिखित की सिफारिश की:

> *"जब लाइसेंसकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर कंपनियों के विलय प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जाता है, तो उसे 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान लाइसेंस के विलय के लिए भी, यदि कोई हो, आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए। दूरसंचार विभाग को NCLT अनुमोदन के बाद लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए लिखित स्वीकृति प्रदान करने के लिए,एक निश्चित समय सीमा जो 30 दिन से अधिक नहीं हो, बतानी चाहिए और इसे दूरसंचार विभाग M&A दिशानिर्देशों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।"*

2.11 परिणामस्वरूप, 24 सितंबर 2018 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक संशोधन के माध्यम से, एकीकृत लाइसेंस के तहत लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण / विलय को मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिनों की समयावधि, दूरसंचार विभाग को उनकी लिखित स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई है।

2.12 कुछ हितधारकों ने कहा है कि यदि एक बार NCLT द्वारा इस योजना को स्वीकृति दे दी जाती है,तो फिर से दूरसंचार विभाग में वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 को संदर्भित करना उपयोगी हो सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार में, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त हों, को देखते हुए भारत के किसी भी हिस्से के भीतर एक टेलीग्राफ को स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए उसे लाइसेंस प्रदान कर सकती है। तदनुसार, दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक कंपनी को लाइसेंस लेना आवश्यक है। जबकि कंपनियों के हस्तांतरण / विलय को NCLT द्वारा अनुमोदित किया जाता है, टेलीकॉम लाइसेंस का हस्तांतरण / विलय लाइसेंसधारक (दूरसंचार विभाग) द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करने

के बाद ही इसका प्रभाव ले सकता है। इस प्रकार, यह कहना उचित नहीं होगा कि एक बार NCLT द्वारा कंपनियों के हस्तांतरण / विलय को मंजूरी दे जाती है,तो लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए दूरसंचार विभाग में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि इस खंड में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

b. मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 3(b) और 3(c)

2.13 मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 3(b) और 3(c) नीचे दिए गए हैं:

"b) न्यायाधिकरण / कंपनी न्यायाधीश द्वारा ऐसी योजना की उपयुक्त स्वीकृति के बाद ऐसे मामलों में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए एक वर्ष की समय अवधि की अनुमति दी जाएगी।

c) यदि कोई लाइसेंसधारी किसी नीलामी में भाग लेता है और फलस्वरूप लॉक-इन स्थिति के अधीन है, तो यदि ऐसा कोई लाइसेंसधारी लागू होने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य लाइसेंसधारी में विलय / समझौता / व्यवस्था / संशोधन करने का प्रस्ताव करता है,तो नए शेयरों के संबंध में आवेदन करने पर जो परिणामी कंपनी (हस्तांतरी कंपनी) के संबंध में जारी किए जाते हैं,तो लॉक-इन अवधि लागू होगी। एक वर्ष की इस अवधि के दौरान पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग क्लॉज तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसे अन्यथा बढ़ाया न जाए। इस अवधि को लिखित में कारणों को दर्ज करके लाइसेंसर द्वारा बढ़ाया जा सकता है।"

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.14 हितधारकों में से एक ने प्रस्तुत किया है कि ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश द्वारा इस तरह की योजना को उचित अनुमोदन के बाद, खंड 3 (b) विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए एक वर्ष की समय अवधि प्रदान करती है। इस खंड को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि किसी भी मुकदमे को आगे बढ़ाने में लगने वाला समय, जिसके विलय की अंतिम मंजूरी दूरसंचार विभाग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जा रही है, एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की गणना करते हुए बाहर रखा गया है। हितधारक ने उल्लेख किया है कि न्यायालय में अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए TSP के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है और यह भी सुनिश्चित करना है कि अदालत के समक्ष किसी मामले के लंबित होने की दशा में TSP की गलती न होते हुए भी एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि निरर्थक न हो जाए।

विश्लेषण

2.15 खंड 3 (b) NCLT द्वारा कंपनियों के विलय के अनुमोदन के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के लिए लाइसेंसधारियों को एक वर्ष की समय अवधि की अनुमति देता है। एक हितधारक ने कहा है कि किसी भी मुकदमे को आगे बढ़ाने में बिताया गया समय, जिसके कारण विलय पर अंतिम अनुमोदन में देरी हो रही है, एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए। हितधारक की दृष्टिकोण पर प्राधिकरण सहमति देता है।

2.16 खंड 3 (c) हस्तांतरकर्ता कंपनी से हस्तांतरी कंपनी तक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के सम्बन्ध में लॉक-इन स्थिति (यदि कोई हो) की जिम्मेदारी को हस्तांतरित करने के लिए प्रदान करता है।

2.17 खंड 3 (c) के दूसरे भाग में आने से पहले, अन्य कंपनियों में इक्विटी होल्डिंग पर एकीकृत लाइसेंस के खंड 42.3 का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"एक्सेस स्पेक्ट्रम रखने / प्राप्त करने की स्थिति में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी लाइसेंसधारी या उसके प्रमोटर को किसी अन्य लाइसेंसधारी कंपनी में उसी सेवा क्षेत्र में "एक्सेस स्पेक्ट्रम" रखने में कोई लाभकारी हित नहीं होगा।"*

2.18 UL के उपरोक्त खंड को देखते हुए, ऐसी स्थिति का ध्यान रखना जहां कंपनियां विलय कर चुकी हैं, लेकिन लाइसेंसों का अभी तक विलय नहीं किया गया है, खंड 3 (c) एक वर्ष की अवधि के दौरान पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग खंड से ऊपर दिए गए खंड 3 (b) या लिखित रूप में लाइसेंसधारक द्वारा विस्तारित, छूट प्रदान करता है।

2.19 वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, यह संभव है कि लाइसेंस का विलय निर्धारित एक वर्ष की अवधि से पहले हो सकता है या इसमें एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है क्योंकि दिशानिर्देशों में एक वर्ष की निर्धारित अवधि में विस्तार का प्रावधान है। हालांकि, खंड 3 (c) एक साल या उससे अधिक की छूट प्रदान करता है। यदि लाइसेंस का विलय एक वर्ष से पहले होता है, तो 6 महीने में कहें, लाइसेंस के विलय से परे पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग खंड के छूट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि इस खंड को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग खंड की प्रयोज्यता से छूट दी जाए जब तक कि अवधि विलय को दूरसंचार विभाग द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है।

2.20 इसके अलावा, दिशा-निर्देशों के खंड 3 (c) का अंतिम वाक्य, यह बताता है कि

लाइसेंसधारक द्वारा लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह अधिक सार्थक हो सकता है यदि लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए अनुमत अवधि के विस्तार के संबंध में खंड 3 (c) का वाक्य उचित रूप से खंड 3 (b) के तहत लाया जाता है क्योंकि यह समयरेखा को परिभाषित करता है।

2.21 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण सिफारिश करता है कि:**

a) न्यायाधिकरण / कंपनी न्यायाधीश (M&A दिशानिर्देशों के खंड 3(b) के अनुमोदन के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए अनुमति दी गई एक वर्ष अर्थात समय अवधि की गणना के लिए, किसी भी दायित्व को आगे बढ़ाने में बिताया गया समय जिसके कारण विलय की अंतिम मंजूरी में देरी हो रही है, उसे गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

b) दिशानिर्देशों के खंड 3 (c) का दूसरा भाग, जो लाइसेंसधारक द्वारा विस्तारित के रूप में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग क्लॉज से छूट प्रदान करता है, को इस तरह संशोधित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त इक्विटी से छूट / क्रॉस होल्डिंग क्लॉज केवल तब तक के लिए प्रदान किया जाए, जब तक लाइसेंस का हस्तांतरण / विलय लाइसेंसधारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है।

c) दिशानिर्देशों के खंड 3 (c) का अंतिम वाक्य, जो कहता है कि ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश की मंजूरी के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए एक वर्ष की अवधि की अनुमति लाइसेंसधारक द्वारा दी जा सकती है लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, इसे उचित रूप से 3 (b) के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि यह समयरेखा को परिभाषित करता है।

c. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(d), 3(e) और 3(f)

2.22 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (d) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "d) *लाइसेंस / प्राधिकरण का विलय संबंधित सेवा श्रेणी के लिए होगा। चूंकि एक्सेस सर्विस लाइसेंस / प्राधिकरण इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान की अनुमति देता है, एक्सेस सेवाओं के लाइसेंस / प्राधिकरण के साथ ISP लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय की भी अनुमति होगी।*
>
> *e) हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी को हस्तांतरी (अधिग्रही) कंपनी द्वारा आयोजित परिसंपत्तियों / लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहीत) कंपनी के लाइसेंस / प्राधिकरण को परिणामी इकाई में नियम के*

अंतर्गत किया जाएगा। परिणामस्वरूप, विभिन्न लाइसेंस / प्राधिकरण की वैधता की तारीख लाइसेंस / प्राधिकरण के अनुसार होगी और उस सेवा के लिए लाइसेंस/प्राधिकरण की विस्तारित अवधि के लिए,तो अनुपात के अनुसार भुगतान यदि कोई हो, के लिए विलय के विषय में दो अवधियों में अधिक के बराबर होगा। । हालाँकि, हस्तांतरणकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी द्वारा रखे गए परिसंपत्ति / लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण के बाद स्पेक्ट्रम की वैधता अवधि अपरिवर्तित रहेगी।

f) किसी भी अतिरिक्त सेवा या किसी भी लाइसेंस क्षेत्र / सेवा क्षेत्र के लिए, संबंधित प्राधिकरण से एकीकृत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।"

विश्लेषण

2.23 जैसा कि खंड 3 (d) से अनुमान लगाया जा सकता है, संबंधित सेवा श्रेणी के लिए लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय की अनुमति है। इसके लिए औचित्य यानी दोनों लाइसेंसधारियों के पास लाइसेंस / सेवा- समान सेवा श्रेणी के लिए प्राधिकरण यह सुनिश्चित करना है कि दो लाइसेंसियों के विलय के कारण परिणामी इकाई की सेवा का दायरा नहीं बदलता है। हालांकि, खंड 3 (d) एक एक्सेस सर्विस लाइसेंसधारी के साथ ISP विलय के लिए एक छूट प्रदान करता है और दिया गया तर्क यह है कि एक्सेस सर्विस लाइसेंसधारक को एक अलग ISP प्राधिकरण / लाइसेंस प्राप्त किए बिना इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।

2.24 खंड 3 (e) प्रदान करता है कि कंपनियों के विलय के मामले में, लाइसेंस की वैधता, उस सेवा के लिए लाइसेंस / प्राधिकरण के विस्तारित अवधि के लिए यथा अनुपात भुगतानों,यदि कोई है, के लिए विलय की तारीख पर दो अवधियों के उच्चतर के बराबर होगी।

2.25 खंड 3 (f) प्रदान करता है कि किसी भी अतिरिक्त सेवाओं के लिए, अपेक्षित प्राधिकरण प्राप्त किया जाना है। सभी TSP लाइसेंसर द्वारा जारी लाइसेंस द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, लाइसेंस / प्राधिकरण का कोई भी स्थानांतरण / विलय लाइसेंस के दायरे को नहीं बदलता है। इसलिए, भले ही इस खंड का उल्लेख M&A दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, यह लाइसेंस समझौते द्वारा लागू किया गया है।

2.26 उपरोक्त खंडों में हितधारकों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं सुझाया गया है। प्राधिकरण को यह भी लगता है कि इन खंडों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

d. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (g)

2.27 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (g) नीचे प्रस्तुत किया गया है:

समझौता, व्यवस्था, कंपनियों के समामेलन के फलस्वरूप लाइसेंसों के स्थानांतरण / विलय की अनुमति दी जाएगी, जहां परिणामी इकाई के संबंधित सेवा क्षेत्र में पहुंच

सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी 50% तक है। विलय या अधिग्रहण या समामेलन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किसी भी सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी में परिणाम 50% से अधिक हो जाता है, परिणामी संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय या अधिग्रहण या समामेलन के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% की सीमा तक कम करना चाहिए । यदि परिणामी निकाय एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक कम करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसकर्ता द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.28 हितधारकों में से एक ने प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि परिणामी इकाई के संबंधित सेवा क्षेत्र में पहुंच सेवाओं के लिए बाजार में हिस्सेदारी 50% तक है 'केवल उस स्थान पर लागू होती है जहां हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी और हस्तांतरी (प्राप्त) कंपनी के पास व्यक्तिगत रूप से दिए गए सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी 50% से कम है। मामले में, या तो हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरी के पास लाइसेंस के स्थानांतरण / विलय से पहले दिए गए सेवा क्षेत्र में 50% से अधिक का बाजार हिस्सा है, उसी को मर्ज किए गए निकाय के बाजार हिस्सेदारी के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए; और 50% तक घटाया जाना अनिवार्य नहीं है।

विश्लेषण

2.29 पिछली बार TRAI ने वर्ष 2011 में M&A पर अपनी सिफारिशें की थीं। 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क' की दिनांक 3 नवंबर 2011 की अपनी सिफारिशों में, TRAI ने अन्य बातों के साथ सिफारिश की थी कि-

"iii. जहां संबंधित बाजार में परिणामी इकाई का बाजार हिस्सा कुल सब्सक्राइबर बेस के 35% या लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में AGR से ऊपर नहीं है, सरकार अपने स्तर पर अनुमति दे सकती है। हालाँकि, जहां, इन दोनों मानदंडों में, यह 35% से अधिक है, लेकिन 60% से नीचे है, सरकार TRAI से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद मामला तय कर सकती है। ऐसे मामले जहां बाजार में हिस्सेदारी 60% से अधिक है, पर विचार नहीं किया जाएगा। " (पैरा 36, अध्याय IV: स्पेक्ट्रम का समेकन)

2.30 TRAI की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, दूरसंचार विभाग ने 2014 में अपना संशोधित M&A दिशानिर्देश जारी किया। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी सेवा क्षेत्र में बाज़ार हिस्सेदारी में विलय प्रस्ताव के परिणाम 50% से अधिक होने पर, ग्राहक आधार या समायोजित राजस्व राजस्व के मामले में परिणामी इकाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय की मंज़ूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक कम कर देना चाहिए, जिसमें विफल होने पर, लाइसेंसकर्ता द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जानी है।

2.31 मौजूदा दिशानिर्देशों में M&A गतिविधि के परिणामस्वरूप 50% बाजार हिस्सेदारी का कैप रखा गया है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि चूंकि सेवाएं प्रदान करके बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कोई कैप नहीं है, तो दो संस्थाओं के विलय के दौरान एक कैप क्यों रखें; इसके अलावा, स्पेक्ट्रम धारण पर एक कैप है, जो प्रतियोगिता के मुद्दों का ध्यान रख सकती है। विपरीत दृष्टिकोण यह हो सकता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा करके एक इकाई विकसित हो सकती है और जैसे ही यह SMP मानदंडों को पूरा करता है, ऐसे प्रतियोगी पर सिग्नीफिकेंट मार्केट पावर (SMP) के सम्बन्ध में नियम लगाये जा सकते हैं; हालांकि, विलय के मामले में, लाइसेंसकर्ता / नियामक की प्रमुख भूमिकाओं में से एक M&A मार्ग के माध्यम से अधिक बाजार की शक्ति और/या पूंजी की शक्ति वाले एक प्रतियोगी को और शक्तिशाली बनने से प्रतिबंधित करना है, क्योंकि यह प्रभुत्व का दुरुपयोग हो सकता है। स्पेक्ट्रम कैप के संबंध में, यह अकेले प्रभुत्व को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यह उस स्पेक्ट्रम पर भी विचार करता है जिसे नीलामी के लिए रखा गया था लेकिन वह अनबिकी रह गई; इसके अलावा, ये दिशानिर्देश एकीकृत लाइसेंस के तहत विभिन्न लाइसेंस / प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम शामिल नहीं हो सकता है।

2.32 एक हितधारक ने प्रस्तुत किया है कि यदि लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय से पहले किसी भी हस्तांतरकर्ता या हस्तांतरी के पास दिए गए सेवा क्षेत्र में 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है, तो उसे विलय किए गए निकाय के बाजार हिस्सेदारी के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए; और 50% तक घटाया जाना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, लाइसेंसर / नियामक की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा हो। स्वस्थ और प्रभावी प्रतिस्पर्धा भी उपभोक्ताओं के हित में है क्योंकि यह गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित करता है। आम तौर पर, M&A दिशानिर्देश बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में एक कट ऑफ पॉइंट निर्धारित करते हैं, जिसके बाहर, एक विलय प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, मौजूदा दिशा-निर्देश एक लचीलापन प्रदान करते हैं जैसे कि यदि कोई TSP इसे लाभकारी पाता है, तो केवल यह M&A के लिए जाएगा। परिणामी इकाई के बाजार में हिस्सेदारी को 50% तक सीमित रखने के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना है कि यदि TSP पहले से ही बाजार में हिस्सेदारी का 50% हिस्सा रखता है, जो कि पर्याप्त है, अर्थात यह पहले से ही एक SMP है, तो M&A गतिविधियों के तहत हतोत्साहित किया जाएगा। एक तरह से, 50% के बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिबंध एक रेड-लाइन के रूप में काम करता है।

2.33 जब तक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स (VNO) की अनुमति नहीं थी, तब तक यह मुद्दा था

कि TSP यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि यह बाजार में हिस्सेदारी खो देता है। हालांकि, जगह में VNO लाइसेंसिंग के साथ, परिणामी इकाई एक VNO के साथ गठजोड़ कर सकती है और अपने बाजार हिस्सेदारी को निकाल सकती है। इस प्रकार, यदि दो लाइसेंसधारी विलय करना चाहते हैं और LSAs में से कुछ में, वे 50% की अनुमत बाजार हिस्सेदारी को पार कर रहे हैं, तो उनके पास अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी को निकाल देने के लिए एक वर्ष की अवधि है और यदि आवश्यक हो, तो वे अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी को निकालने में VNO से संलग्न हो सकते हैं। इससे बाजार में पर्याप्त संख्या में प्रतियोगियों को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में, UL(VNO) के निम्नलिखित खंड को संदर्भित करना उपयोगी हो सकता है:

> *"1.3 लाइसेंसधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि:*
> *(i) शेयरधारिता में कोई भी बदलाव भारत के कानून के तहत सभी लागू वैधानिक अनुमतियों के अधीन होगा।*
>
> *(ii) प्रति सेवा क्षेत्र में VNO लाइसेंसधारियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। VNOs को एक्सेस सेवा और ऐसी सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं के लिए एक से अधिक NSO के साथ समझौते करने की अनुमति है, जिन्हें नंबरिंग और ग्राहक की विशिष्ट पहचान की आवश्यकता होती है। EPABX के माध्यम से वायर लाइन एक्सेस सेवाओं के लिए, विभिन्न EPABX पर विभिन्न NSO की कनेक्टिविटी की अनुमति है, हालांकि, एक विशेष EPABX पर एक से अधिक NSO के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाएगी। UL(VNO) में इक्विटी क्रॉस होल्डिंग के प्रतिबंध का प्रावधान (i) एक VNO या इसके प्रमोटर और एक अन्य NSO (VNO के पैरेंट NSO के अलावा) या इसके प्रमोटर और (ii)VNO या इसके प्रमोटर और एक अन्य VNO या इसके प्रमोटर के बीच लागू होगा , एक ही सेवा क्षेत्र में NSO(s) के एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। यह प्रतिबंध समान NSO से पेरेंटेड VNO के मामले में लागू नहीं होगा। NSO के लिए अपने VNO के लिए समयबद्ध पहुँच प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि, यह एक NSO और VNO के बीच आपसी समझौते पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, उपभोक्ताओं के दूरसंचार क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए TRAI / दूरसंचार विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।"*

2.34 उपरोक्त खंड से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध VNO और उसके मूल NSO के बीच लागू नहीं है। इस प्रकार, एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक VNO में पर्याप्त इक्विटी वाले NSO सरप्लस मार्केट शेयर पर VNO के रूप में अपने स्वयं के हाथ में गुजरता है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए, प्राधिकरण का विचार है कि यदि VNO के प्रवर्तक के रूप में NSO के प्रवर्तक हैं, तो VNO की बाजार हिस्सेदारी को पैरेंट NSO के मार्केट शेयर में गिना जाना चाहिए। इसलिए, **प्राधिकरण की सिफारिश है कि संबंधित बाजार में एक NSO की बाजार हिस्सेदारी की गणना करने के लिए, इसके साथ VNO के बाजार में हिस्सेदारी को NSO के बाजार हिस्सेदारी में जोड़ा जाना चाहिए, अगर NSO, VNO का प्रमोटर है। एक प्रमोटर की परिभाषा लाइसेंस के**

लाइसेंस / दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगी।

e. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(h)

2.35 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (h) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"उपरोक्त बाजार में हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए, सब्सक्राइबर बेस और संबंधित बाजार में लाइसेंसधारी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) दोनों के मार्केट शेयर पर विचार किया जाएगा। संपूर्ण एक्सेस मार्केट मार्केट शेयर का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक बाजार होगा जिसमें वायरलाइन साथ ही वायरलेस सब्सक्राइबर शामिल होगा।एक्सचेंज डेटा रिकॉर्ड्स (EDR) का उपयोग वायरलाइन ग्राहकों की गणना में किया जाएगा और सब्सक्राइबर बेस के आधार पर मार्केट शेयर की गणना के उद्देश्य से वायरलेस सब्सक्राइबर्स की गणना के लिए वायरलाइन लोकेशन रजिस्टर (VLR) डेटा या समकक्ष की गणना की जाएगी। EDR/ VLR आंकड़ों को ध्यान में रखने के लिए संदर्भ तिथि, आवेदन की तिथि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर या 30 जून तक होगी। विधिवत लेखा परीक्षित AGR प्रासंगिक बाजार में ऑपरेटरों के लिए राजस्व आधारित बाजार हिस्सेदारी की गणना का आधार होगा। AGR की विधिवत लेखा परीक्षा की तारीख पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च होगी।"*

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.36 हितधारकों में से एक ने टिप्पणी की है कि वर्तमान में, विलय दिशानिर्देश CMTS/UASL/ यूनिफाइड लाइसेंस (एक्सेस सेवा प्राधिकरण के साथ) रखने वाले ऑपरेटरों तक सीमित हैं; इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि अन्य सेवा प्राधिकरणों जैसे NLD, ILD, VSAT, ISP, आदि के लिए विलय दिशानिर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

विश्लेषण

2.37 जबकि मौजूदा दिशानिर्देश सभी लाइसेंस / प्राधिकरणों के लिए लागू होते हैं, खंड 3 (h) के माध्यम से बनाए गए प्रावधान एक्सेस सर्विस लाइसेंसर्स को देखते हुए बनाए गए हैं। कुछ सेवाओं में, सब्सक्राइबर के संदर्भ में बाजार हिस्सेदारी पर विचार करना उचित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक NLD सेवा प्रदाता कई सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसे कि (i) LSAs में वॉइस ट्रैफिक ले जाना, (ii) घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करना, (iii) SLA आधारित MPLS सेवाएं प्रदान करना; जबकि होम LSA के बाहर समाप्त होने वाले एक्सेस सर्विस प्रोवाइडरों के ग्राहकों की सभी आवाज ट्रैफिक को NLD सेवा प्रदाता द्वारा दी जाती है,DLC और MPLS सेवाओं का उपयोग एंटरप्राइज ग्राहकों द्वारा किया जाता है, जहां एक उद्यम ने कई कनेक्शन (DLCs और / या MPLS) लिए होंगे। एक दृष्टिकोण बाजार हिस्सेदारी की गणना करने के लिए एक TSP द्वारा पट्टे पर ली गई क्षमता का उपयोग करने के लिए हो सकता है; हालाँकि, समर्पित लीज्ड सर्किट

क्षमता के साथ-साथ दूरी के भी कारक हैं। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि ग्राहक आधार और AGR के दौरान, दोनों एक्सेस, इंटरनेट, VSAT, GMPCS, PMRTS, और INSAT MSS-R; के लिए प्रासंगिक होंगे; बाकी सेवाओं के लिए, बाजार हिस्सेदारी की गणना के लिए AGR एकमात्र कारक है।

2.38 इसलिए, **प्राधिकरण का सुझाव है कि दिशानिर्देशों के खंड 3 (h) में इस तरह संशोधन किया जा सकता है:**

(a) एक्सेस, इंटरनेट, VSAT, GMPCS, PMRTS, और INSAT MSS-R सेवा लाइसेंस/प्राधिकरण के लिए बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए, ग्राहकों की संख्या और साथ ही AGR दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

(b) सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण यानी NLD, ILD और IPLC का पुनर्विक्रय,के बाकी हिस्सों के लिए बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए केवल AGR पर विचार किया जाना चाहिए।

f. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (i)

2.39 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (i) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"i) I) यदि कोई हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा रखती है, जो (4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज) को प्रवेश शुल्क के खिलाफ सौंपा जाता है, तो हस्तांतरी (अधिग्रहण) कंपनी (यानी परिणामी विलय इकाई), विलय के समय सरकार को लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश द्वारा ऐसी व्यवस्था के अनुमोदन की तारीख से प्रवेश शुल्क और बाजार के बीच स्पेक्ट्रम की निर्धारित अंतर के कीमत का भुगतान करेगी। लाइसेंस को वर्ष 2010 से नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा।चूंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी निर्धारित मूल्य एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, उसके बाद, भारतीय स्टेट बैंक दरों पर PLR को एक वर्ष की अवधि के बाद बाजार निर्धारित मूल्य पर पहुंचने के लिए अंतिम नीलामी निर्धारित मूल्य में जोड़ा जाएगा। स्पेक्ट्रम होल्डिंग के संबंध में एक समय स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए उठाए गए मांगों के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति में हस्तांतरी के संबंध में विलय से पहले CDMA बैंड में 4.4 मेगाहर्ट्ज GSM बैंड/ 2.5 मेगाहर्ट्ज से (यानी) अधिग्रहण इकाई) कंपनी, एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए विभाग द्वारा की गई मांग के बराबर एक बैंक गारंटी अदालत के मामले के अंतिम परिणाम लंबित प्रस्तुत किया जाएगा।"

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.40 कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि खंड 3 (i) के अनुसार, आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनियों को हस्तांतरी कंपनी के संबंध में एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार की बकाया मांग के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह अनुचित है कि यदि एक बार TSPs

द्वारा किसी अदालत में एक विशेष मांग को चुनौती दी जाती है और उन्होंने इस तरह की मांग के खिलाफ स्थगन प्राप्त कर लिया है,तो बैंक गारंटी के माध्यम से इसे सुरक्षित करने के लिए कहा जा रहा है। नतीजतन, विलय करने वाली संस्थाएं विलय की मंजूरी से पहले या बाद में ऐसी मांग को चुनौती देने के लिए मजबूर होती हैं और इससे कई मुकदमे होते हैं। इसलिए, इस विशेष आवश्यकता को विलय के दिशानिर्देशों से हटा दिया जाना चाहिए।

2.41 एक हितधारक ने बताया कि खंड 3 (i) हस्तांतरी कंपनी की स्पेक्ट्रम होल्डिंग के लिए बैंक गारंटी की मांग करता है, जो दिशानिर्देशों में गलती लगती है।

विश्लेषण

2.42 खण्ड 3(i) का पहला भाग यह प्रदान करता है कि यदि कोई हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा रखती है (GSM/CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज), जिसे भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क, हस्तांतरी (अधिग्रहण) के एवज में सौंपा गया है कंपनी (अर्थात परिणामी विलय इकाई), विलय के समय, सरकार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण / कंपनी न्यायाधीश द्वारा लाइसेंस की वैधता की शेष अवधि के लिए अनुपात के आधार पर , लाइसेंस के साथ सह-सीमावर्ती होने वाले स्पेक्ट्रम की वैधता के ऐसी व्यवस्था के अनुमोदन की तिथि से स्पेक्ट्रम के प्रवेश शुल्क का भुगतान और बाजार निर्धारित मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करेगी।

2.43 यह समझना उपयोगी होगा कि प्रवेश शुल्क और स्पेक्ट्रम के बाजार निर्धारित मूल्य के बीच अंतर GSM/CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम के लिए क्यों कहा जा रहा है। पहले के समय में, जब स्पेक्ट्रम को लाइसेंस के साथ बंडल किया गया था, TSPs को प्रारंभिक स्पेक्ट्रम (GSM/CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज) सौंपा गया था, साथ ही प्रवेश शुल्क के भुगतान के खिलाफ लाइसेंस और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उन्हें ग्राहक से जुड़े मानदंडों के आधार पर;प्रशासनिक रूप से सौंपा गया था, हालांकि, इस तरह के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए TSPs से कोई कीमत नहीं ली गई थी। विलय के परिणामस्वरूप, हस्तांतरकर्ता कंपनी द्वारा आयोजित प्रशासनिक रूप से आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम (प्रारंभिक स्पेक्ट्रम + प्रशासनिक रूप से सौंपा गया अतिरिक्त स्पेक्ट्रम) हाथों को बदल रहा है (हस्तांतरी कंपनी को हस्तांतरित हो रहा है); इस प्रकार, बाजार के निर्धारित मूल्य का भुगतान करके इसे उदार बनाया जाना चाहिए। इसलिए, दिशानिर्देश अनुपात के आधार पर स्पेक्ट्रम की वैधता के शेष अवधि के लिए NCLT के अनुमोदन की तारीख से स्थानांतरण कंपनी द्वारा आयोजित किसी भी प्रारंभिक स्पेक्ट्रम (GSM/CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज तक) के लिए

प्रवेश शुल्क और बाजार निर्धारित मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने के लिए निर्धारित करते हैं। हस्तांतरी कंपनी द्वारा आयोजित किसी भी प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के लिए, सही, दिशा-निर्देश प्रवेश शुल्क भुगतान और बाजार निर्धारित मूल्य के बीच के अंतर की तलाश नहीं करते हैं क्योंकि वही हाथ नहीं बदल रहा है। एक बार एक सेवा प्रदाता बाजार के निर्धारित मूल्य के बराबर भुगतान करता है,तो ऐसे स्पेक्ट्रम को उदारीकृत अर्थात् प्रौद्योगिकी तटस्थ के रूप में माना जाना चाहिए ; हालाँकि, स्पेक्ट्रम के उदारीकरण पर दिशानिर्देश वर्ष 2015 (M&A के दिशानिर्देशों के बाद में) के मुद्दे थे, M&A दिशानिर्देशों में इसके बारे में उल्लेख नहीं है।इसलिए, **प्राधिकरण की सिफारिश है कि यह स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों में उल्लेख किया जाना चाहिए कि परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम के लिए बाजार निर्धारित मूल्य के भुगतान पर, ऐसे स्पेक्ट्रम को उदारीकृत माना जाएगा।**

i. e. प्रौद्योगिकी तटस्थ।

2.44 आगे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लाइसेंसकर्ता की लिखित स्वीकृति के बाद ही एक विलय प्रभावी होता है, जिसके लिए दिशानिर्देशों में एक वर्ष का समय ही प्रदान किया गया है, वह भी लाइसेंसर द्वारा कारणों को दर्ज करने के बाद बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, परिणामी इकाई विलय के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर ही विलय के लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगी (हस्तांतरणकर्ता कंपनी के स्पेक्ट्रम होल्डिंग सहित)। इसलिए, विलय की गई इकाई को दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदन की तारीख से ट्रांसफर कंपनी के प्रवेश शुल्क के एवज में आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए अंतर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इस मुद्दे पर 'ईज ऑफ डूइंग टेलीकॉम बिजनेस' पर परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में चर्चा की गई थी और यह सिफारिश की गई थी कि अंतर राशि NCLT द्वारा अनुमोदन की तारीख के बजाय दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदन की तारीख से देय होनी चाहिए। इसके पीछे संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित विकल्प का सुझाव दिया, जिसे TRAI ने सहमति दी; हालाँकि, अभी तक इस संबंध में कोई संशोधन जारी नहीं किया गया है।

> *"जब लाइसेंसकर्ता दूरसंचार विभाग में लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए आवेदन करता है, दूरसंचार विभाग NCLT अनुमोदन की तारीख से वन टाइम स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) के हस्तांतरी की मांग उठाएगा, इस शर्त के साथ कि ऐसी मांग दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस के हस्तांतरण की मंजूरी के बाद संशोधन के अधीन है।अनुदान की तारीख के अनुमोदन के आधार पर OTSC के मांग की पुनर्गणना होगी। भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, हस्तांतरी को वापस/ अन्य बकाया राशि के विरुद्ध सेट ऑफ कर दी जाएगी।"*

2.45 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण ने अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराया है कि यदि कोई हस्तांतरणकर्ता कंपनी स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा रखती है, जिसे भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के एवज में सौंपा गया है, तो हस्तांतरी कंपनी / परिणामी इकाई को स्पेक्ट्रम के लिए जिसे हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के एवज में सौंपा गया है,दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस के हस्तांतरण/ विलय की लिखित स्वीकृति की तारीख से अंतर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। हालांकि, अंतर राशि के भुगतान की मांग को बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग NCLT अनुमोदन की तारीख से अस्थायी मांग की गणना करेगा, और विलय की मंजूरी मिलने पर, अनुमोदन राशि के अनुमोदन की तिथि के आधार पर अंतर राशि की वास्तविक मांग की पुनर्गणना की जाएगी। हस्तांतरी कंपनी / परिणामी संस्था द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, हस्तांतरी कंपनी / परिणामी संस्था को वापस कर दी जाएगी या अन्य देय राशि के विरुद्ध सेट कर दी जाएगी।**

2.46 खंड 3 (i) का दूसरा भाग यह बताता है कि विलय से पहले हस्तांतरी कंपनी के सम्बन्ध में GSM/CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्टज / 2.5 मेगाहर्टज से आगे स्पेक्ट्रम होल्डिंग के संबंध में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (OTSC) के लिए उठाए गए मांगों के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप के मामले में, समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। आगे चर्चा करने से पहले, OTSC को समझना उपयोगी हो सकता है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, पहले के समय में, जब स्पेक्ट्रम को लाइसेंस के साथ बंडल किया गया था, TSPs को प्रारंभिक स्पेक्ट्रम (GSM/ CDMA के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज) सौंपा गया था, साथ ही ग्राहक से जुड़े मानदंडों के आधार पर उन्हें प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया था और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम सौंपा गया था; हालांकि, इस तरह के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए TSPs से कोई कीमत नहीं ली गई थी। इसलिए, 2012 के अपने आदेश के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने TSP को आदेश दिया कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें, पूर्वव्यापी रूप से सौंपे गए मूल्य का भुगतान करें, और इस मूल्य को OTSC कहा गया। TSPs(अलग से) ने दूरसंचार विभाग के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी क्योंकि उस समय TDSAT कार्यात्मक नहीं था। इन याचिकाओं में से कुछ को उच्च न्यायालय ने TDSAT के लिए अधिमानित किया था। इनमें से कुछ याचिकाओं में, TDSAT ने अपना आदेश दिया है और दूरसंचार विभाग ने TDSAT आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसने TDSAT आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला न्यायाधीन है।

2.47 विलय के समय, आदर्श रूप से, बाजार की निर्धारित कीमत किसी भी प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए शेष वैधता के लिए विलय की तारीख से विलयकर्ता कंपनी

द्वारा आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि यह हस्तांतरी कंपनी को हस्तांतरित हो रही है। हालाँकि, चूंकि दूरसंचार विभाग ने GSM / CDMA के लिए 4.4 MHz / 2.5 MHz से परे प्रशासनिक रूप से असाइन किए गए स्पेक्ट्रम के संबंध में OTSC (जिसमें विलय से पहले की अवधि भी शामिल है) की मांग पहले ही बढ़ा दी है, दिशा-निर्देश OTSC के लिए मांग की गई राशि के बराबर बैंक गारंटी की मांग करते हैं, लेकिन हस्तांतरी कंपनी के संबंध में हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लिए नहीं। यह हस्तांतरणकर्ता कंपनी की स्पेक्ट्रम होल्डिंग है जो हाथों को बदल रही है और हस्तांतरी कंपनी की नहीं। जाहिर है, कुछ त्रुटि है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि धारा 3 (i) के अंतिम वाक्य में "हस्तांतरी (यानी अधिग्रहण करने वाली कंपनी)" को "हस्तांतरणकर्ता कंपनी (यानी अधिग्रहित कंपनी)" से बदल दिया जाना चाहिए।

2.48 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण सिफारिश करता है कि धारा 3 (i) के अंतिम वाक्य में "हस्तांतरी (यानी अधिग्रहण करने वाली कंपनी)" को "हस्तांतरकर्ता कंपनी (यानी अधिग्रहित कंपनी)" से बदल दिया जाना चाहिए।**

2.49

g. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(j)

2.50 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(j) नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> *"स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज (SUC) जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, परिणामी इकाई के कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर भी देय होगा।"*

2.51 स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सरकार द्वारा समय-समय पर अलग से निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न नीलामी के माध्यम से अधिग्रहित स्पेक्ट्रम के लिए विभिन्न SUC दरें लागू होती हैं। 2016 में आयोजित अंतिम नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम पर SUC को वायरलाइन सेवाओं से राजस्व को छोड़कर AGR के 3% की दर से वसूला गया है। एक ऑपरेटर को सौंपे गए एक्सेस स्पेक्ट्रम के संयोजन के मामले में (चाहे प्रशासनिक रूप से या नीलामी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से सौंपा गया हो), TSP को सौंपे गए सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम में SUC दरों का भारित औसत TSP द्वारा आयोजित पूरे एक्सेस स्पेक्ट्रम पर लागू होता है। दिशानिर्देशों का खंड 3 (j), निर्धारित करता है कि SUC निर्धारित के रूप में, परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल SUC पर देय होगा।इस खंड पर हितधारकों से कोई टिप्पणी नहीं मिली है। प्राधिकरण का भी यह विचार है कि इस खंड में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

एक समय निर्धारित शुल्क के अनुसार 6.2 मेगाहर्ट्ज (GSM) से ऊपर स्पेक्ट्रम के लिए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (OTSC) (प्रवेश शुल्क और बाजार निर्धारित मूल्य के बीच अंतर के आधार पर) का भुगतान करने के लिए और 4.4 मेगाहर्ट्ज (GSM) से ऊपर स्पेक्ट्रम धारण के लिए, TSPs को 1.1.2013 के प्रभाव से OTSC का भुगतान या 4.4 मेगाहर्ट्ज से परे स्पेक्ट्रम का आत्मसमर्पण करने का विकल्प दिया गया था । इसी तरह का आदेश CDMA सेवाओं के लिए 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 मेगाहर्टज से परे स्पेक्ट्रम होल्डिंग के लिए जारी किया गया था।

h. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (k)

2.52 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3(k) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"एक समझौते के तहत योजना, व्यवस्था या समामेलन और एक सेवा क्षेत्र में लाइसेंस के विलय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम कैप के संबंध में निम्नलिखित शर्तें परिणामी इकाई पर लागू होंगी।

(i) परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में, नीलामी के माध्यम से या अन्यथा पहुंच सेवाओं के लिए निर्दिष्ट कुल स्पेक्ट्रम का 35% से अधिक नहीं होगा।

(ii) परिणामी निकाय द्वारा उप -1 गीगाहर्ट्ज बैंड (700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड) में नीलामी या अन्यथा, संबंधित सेवा क्षेत्र में संयुक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग उप -1 गीगाहर्ट्ज बैंड में सौंपे गए कुल स्पेक्ट्रम के 50% से अधिक नहीं होगी।

(iii) स्पेक्ट्रम कैप की गणना के लिए अगस्त 2016 के एनआईए में लागू किए गए सिद्धांतों को संशोधित किए जाने के साथ-साथ उप-1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कैप की गणना करते समय भी लागू किया जाएगा।

(iv) यदि हस्तांतरकर्ता और हस्तांतरी कंपनी को 2010 में 3 जी / बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित नीलामी के माध्यम से 3 जी स्पेक्ट्रम (2100 मेगाहर्ट्ज) का एक ब्लॉक आवंटित किया गया था, परिणामी इकाई को कंपनियों के समझौते, व्यवस्था और समामेलन के परिणामस्वरूप संबंधित सेवा क्षेत्रों में उपर्युक्त नीलामी के माध्यम से अधिग्रहित और एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण और विलय के परिणामस्वरूप 3 जी स्पेक्ट्रम (2100 मेगाहर्ट्ज) के दो ब्लॉकों को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।"

हितधारकों से टिप्पणियाँ

2.53 इस खंड पर हितधारकों से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

विश्लेषण

2.54 स्थानांतरण/विलय पर लाइसेंस के मौजूदा दिशा-निर्देश मौजूदा स्पेक्ट्रम कैप को हार्ड-कोड करते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 29 सितंबर 2017 के अपने पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने TRAI से स्पेक्ट्रम कैप पर अपने विचार प्रदान करने का अनुरोध किया था। दिनांक 21 नवंबर 2017 को दूरसंचार विभाग के जवाब में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

(i) समग्र स्पेक्ट्रम कैप को 25% की वर्तमान सीमा से 35% तक संशोधित किया जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान इंट्रा-बैंड कैप को हटाया जाना चाहिए। इसके बजाय, सब -1 गीगाहर्ट्ज बैंड (700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड) में संयुक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर 50% की कैप होनी चाहिए।

2.55 इसके बाद, 19 मार्च 2018 को, दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस में संशोधन जारी किया और स्पेक्ट्रम आवंटन और उपयोग के भाग I के अध्याय VII के तहत 'स्पेक्ट्रम धारण के लिए कैप की सीमा' पर खंड 42.11 को जोड़ा। संशोधित स्पेक्ट्रम कैप्स को शामिल करने के लिए 30 मई 2018 को दूरसंचार विभाग द्वारा M&A दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

2.56 1 अगस्त 2018 के विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से, प्राधिकरण ने अन्य के साथ स्पेक्ट्रम बैंड 3300-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए निम्नलिखित की सिफारिश की है:

"…. इस बैंड के एकाधिकार से बचने के लिए, प्रति बोलीदाता 100 मेगाहर्ट्ज की सीमा होनी चाहिए। चूंकि TSP को अपने आंशिक या पूर्ण स्पेक्ट्रम धारण को किसी अन्य TSP के साथ व्यापार करने की अनुमति है, 3300-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की सीमा, स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए भी लागू होगी।"

2.57 अब उस स्पेक्ट्रम कैप को लाइसेंस में ही शामिल कर लिया गया है, और लाइसेंस में कोई भी बदलाव निश्चित रूप से परिलक्षित होगा, यह लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय पर दिशानिर्देशों में हार्ड कोडिंग के बजाय लागू स्पेक्ट्रम कैप को यूएल के संबंधित धारा के साथ जोड़ने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

2.58 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण का सुझाव है कि लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय पर दिशानिर्देश स्पेक्ट्रम कैप को हार्ड-कोड नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, इसे लाइसेंस के संबंधित धारा के साथ जोड़ा जाना चाहिए।**

i. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (I)

2.59 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (I) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"यदि विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से परे है, तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को आत्मसमर्पण करना चाहिए या अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के भीतर कारोबार करना होगा। लागू स्पेक्ट्रम उपयोग, कुल स्पेक्ट्रम धारण पर परिणामी इकाई को ऐसी अवधि के लिए प्रभार लगाया जाएगा। यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण या कारोबार नहीं करता है, तो, ऐसे मामलों में संबंधित लाइसेंस / वैधानिक प्रावधानों के तहत अलग-अलग कार्रवाई, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के गैर-आत्मसमर्पण / गैर-व्यापार के लिए सरकार द्वारा की जा सकती है। हालांकि, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए और / या देय पैसे का कोई वापसी या सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।"

हितधारकों से टिप्पणियाँ

2.60 इस खंड पर हितधारकों से कोई टिप्पणियाँ नहीं मिली है।

2.61 **Analysis** 24 सितंबर, 2018 तक, इस खंड में स्पेक्ट्रम व्यापार के माध्यम से स्पेक्ट्रम धारण को कम करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस मुद्दे को प्राधिकरण ने "ईज ऑफ डूइंग टेलीकॉम बिजनेस" पर अपनी सिफारिशों के हिस्से के रूप में जांचा था, जिसमें यह पाया गया था कि 20 फरवरी 2014 को लाइसेंस के स्थानांतरण / विलय पर दिशानिर्देश जारी करने के समय,देश में स्पेक्ट्रम व्यापार की अनुमति नहीं थी। इसलिए, केवल अतिरिक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग से छुटकारा पाने का प्रावधान लाइसेंसधारक के लिए उसका आत्मसमर्पण था जिसमें अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए धन और / या देय धन वापसी या सेट-ऑफ का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, प्राधिकरण ने, "ईज ऑफ डूइंग टेलीकॉम बिजनेस" पर अपनी सिफारिशों के हिस्से के रूप में, अन्य बातों के साथ सिफारिश की

> *"अगर विलय की अनुमति अनुमेय स्पेक्ट्रम कैप से अधिक स्पेक्ट्रम धारण में है, तो परिणामी इकाई को एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अपने स्पेक्ट्रम होल्डिंग को आत्मसमर्पण या व्यापार करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण का विचार है कि दूरसंचार विभाग के M&A दिशानिर्देशों के खंड 3 (L) को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।"*

2.62 नतीजतन, 24 सितंबर 2018 को DoT द्वारा जारी किए गए एक संशोधन के माध्यम से, स्पेक्ट्रम 3 के व्यापार के लिए प्रावधान खंड 3 (I) में निर्धारित किया गया था। चूंकि इस प्रावधान की हाल ही में जांच की गई थी और DoT ने लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय पर दिशानिर्देशों में अपेक्षित संशोधन किया है, इसलिए इसमें अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

j. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (m)

2.63 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (m) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"m) विलय की संस्थाओं के लाइसेंस से संबंधित सभी मांगों, यदि कोई हो, तो लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय / हस्तांतरण की अनुमति जारी करने से पहले दोनों लाइसेंसधारियों में से किसी एक को स्वीकृति देनी होगी।। यह किसी लंबित कानूनी मामलों या विवादों के बावजूद कंपनी द्वारा दायर रिटर्न के आधार पर सरकार / लाइसेंसकर्ता द्वारा की गई मांग के अनुसार होगा। परिणामी इकाई द्वारा इस आशय की एक प्रविष्टि प्रस्तुत की जाएगी कि अंतरण या स्थानान्तरी कंपनी के पूर्व-विलय अवधि के लिए किसी भी मांग का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, विधिक न्यायालय द्वारा हस्तांतरकर्ता और स्थानान्तरी कंपनी के एक बार के स्पेक्ट्रम शुल्क को छोड़कर मांगें, इस तरह के मुकदमेबाजी के निर्णय के परिणाम के अधीन होंगी। इन दिशानिर्देशों के ऊपर पैरा 3 (i) में प्रावधानों के अनुसार एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क देय होगा। "*

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.64 एक हितधारक ने प्रस्तुत किया है कि खंड 3 (m) के अनुसार सभी मांगें, यदि कोई हो, तो विलय करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस से संबंधित, दोनों में से किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा विलय / डिमर्जर की अनुमति से पहले मंजूरी देनी आवश्यक है। वर्तमान में, दूरसंचार विभाग इन-प्रिंसिपल और अंतिम विलय अनुमोदन दोनों के समय बकाया राशि की निकासी चाहता है। बकाए की निकासी की पूरी प्रक्रिया काफी बोझिल है और विलय की प्रक्रिया में बड़ी देरी का कारण बनती है। हितधारक द्वारा निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है:

(i) दूरसंचार विभाग को स्थानान्तरणकर्ता कंपनी और स्थानान्तरी कंपनी दोनों के लिए बकाया राशि की निकासी के लिए जोर नहीं देना चाहिए, यह देखते हुए कि सभी देनदारियों को स्थानान्तरी कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है;

(ii) यदि बकाया राशि को साथ में ही खत्म करना है, तो इसे एक निश्चित तिथि के लिए होना चाहिए, जिस पर बकाया राशि को खत्म करने की आवश्यकता है और यह NCLT द्वारा विलय की अंतिम मंजूरी से पहले होना चाहिए;

(iii) विचाराधीन मामलों की एक सुसंगत परिभाषा बताई गई है, ताकि विलय करने वाली संस्थाएँ विचाराधीन मामलों के लिए लेकिन जिनकी अलग तरीके से व्याख्या की गई हो, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न हों ;

(iv) दूरसंचार विभाग की सभी आपत्तियाँ कई बार नहीं बल्कि एक बार उठाई जाए।

2.65 एक अन्य हितधारक ने कहा कि बकाया मांगों की सूची को उसी तिथि के रूप में लिया जाना चाहिए, दूरसंचार विभाग पहले सिद्धांत अनुसार अनुमोदन जारी करता है, जिसे NCLT को प्रस्तुत किया जाता है। सुविधाजनक लेन-देन को सक्षम करने के लिए सूची को खुला नहीं रखा जाना चाहिए।

Analysis

2.66 दो हितधारकों ने प्रस्तुत किया है कि बकाए की सूची को खुला नहीं रखा जाना चाहिए, इसके लिए एक निश्चित तिथि होनी चाहिए, जिस पर बकाए को खत्म करना आवश्यक हो और यह NCLT द्वारा विलय की अंतिम मंजूरी से पहले होना चाहिए। एक हितधारक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि दूरसंचार विभाग को कई बार नहीं बल्कि एक बार हीं सभी आपत्तियों और बकाया राशि को उठाना चाहिए।

2.67 M&A दिशानिर्देशों का खंड 3 (m) यह प्रदान करता है कि सभी मांगें, यदि कोई हो, विलय संस्थाओं के लाइसेंस से संबंधित है, तो लाइसेंस/प्राधिकरण के विलय / हस्तांतरण की अनुमति जारी करने से पहले दोनों लाइसेंसधारियों में से किसी एक को मंजूरी देनी होगी। यह समझा जाता है कि लाइसेंसकर्ता द्वारा उठाई गई कोई भी मांग निर्धारित समयसीमा के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा देय है, यह विलय का मामला हो सकता है या नहीं। इस प्रकार, प्राधिकरण हितधारकों की टिप्पणियों में कोई योग्यता नहीं पाता है। इसलिए, मौजूदा खंड में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

k. मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (n)

2.68 मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 3 (n) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"यदि किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई एक "सिग्नीफिकेंट मार्केट पावर "(एसएमपी) बन जाती है, तो एसएमपी पर लागू होने वाले मौजूदा नियम और नियम भी परिणामी इकाई पर लागू होंगे। पहुँच सेवाओं के संबंध में एसएमपी को ट्राई के "टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्ट (रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर) विनियम, 2002 (2002 का 2) में परिभाषित किया गया है।"*

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.69 इस खंड के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

विश्लेषण

2.70 खण्ड 3 (n) में वर्णित है कि यदि परिणामी इकाई एसएमपी बन जाती है, तो नियम और विनियमन, जैसा कि लागू होता है, परिणामी इकाई पर लागू होगा।

2.71 हितधारकों ने इस खंड में किए जाने वाले किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं दिया है। प्राधिकरण का भी यह विचार है कि इस खंड में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

C. VNOAI का प्रतिनिधित्व

2.72 दिनांक 11 जून 2019 को अपने पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (VNOAI) से दिनांक 16.11.2018 को प्राप्त प्रतिनिधित्व की एक प्रति भी अग्रेषित की थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देशों, 2014 में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करते समय इस पर विचार किया जा सकता है। अपने पत्र में, VNOAI ने, अन्य बातों के साथ, कार्टेलाइजेशन से बचने और विलय किए गए निकाय के लिए MVNOs / VNOs को अनिवार्य करके प्रतियोगिता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का विवरण प्रदान किया। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, VNOAI ने मोबाइल बिटस्ट्रीम एक्सेस (MBA) आधार पर MVNOs के लिए थोक क्षमता का 20% अलग सेट करने के लिए विलय किए गए निकाय पर एक प्रतिबद्धता लगाने का सुझाव दिया है। इस संबंध में, VNOAI ने यूरोपीय आयोग से अंतरराष्ट्रीय पूर्व उदाहरण का हवाला दिया है, जिसमें अधिकारियों ने बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए MVNOs के लिए थोक क्षमता एक ओर रखना अनिवार्य कर दिया है।

2.73 MVNOs के लिए अनिवार्य पहुंच के संबंध में, यह पाया गया कि VNOAI द्वारा उद्धृत सभी तीन अंतरराष्ट्रीय मामलों में, प्रतिबद्धता, जो, अन्य बातों के साथ ,जिसमें MVNOs तक पहुंच प्रदान करना MNO और यूरोपीय आयोग की प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (CAEC) द्वारा प्रस्तावित था,शामिल है।

i. e. महानिदेशक प्रतियोगिता ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित विलय,प्रतिबद्धताओं के पूर्ण अनुपालन के अधीन, अब प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा, MVNOs के लिए अनिवार्य पहुंच एक स्टैंडअलोन उपाय नहीं था, बल्कि एक व्यापक उपाय पैकेज का एक हिस्सा था जिसमें स्पेक्ट्रम का विभाजन आदि भी शामिल था। यूरोपीय उपाय एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के माध्यम से एक विस्तृत पर्यवेक्षी प्रक्रिया के साथ-साथ MVNO और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर (या पहुँच प्रदान करने वाली विलय इकाई) के बीच किसी भी विवाद से बचने के लिए MVNOs को थोक पहुंच के प्रावधान के लिए प्रमुख वाणिज्यिक सिद्धांतों और शुल्कों को भी परिभाषित करता है। इस प्रकार, यह कहना गलत नहीं होगा कि MVNOs तक पहुंच CAEC द्वारा अनिवार्य नहीं थी, लेकिन मामले के आधार पर विलय के प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान

सहमति व्यक्त की गई थी।

2.74 इस संबंध में, हितधारकों को इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्या प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को दूर करने के लिए MVNOs को अनिवार्य पहुँच को दूरसंचार विभाग M&A दिशानिर्देशों में प्रावधानित किया जाना चाहिए।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.75 कई हितधारकों ने प्रस्तुत किया है कि M&A दिशानिर्देश MVNOs को अनिवार्य पहुंच के लिए प्रदान नहीं करना चाहिए। हितधारकों ने यह भी उल्लेख किया कि MVNOs को वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर पहुंच प्राप्त करने के लिए आवश्यक होना चाहिए और एक से अधिक सेवा प्रदाता की उपलब्धता को देखते हुए, बाजार की गतिशीलता को शर्तों के बराबर होने की अनुमति देनी चाहिए। यदि प्राधिकरण का विचार है कि MVNOs को अनिवार्य पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, तो इसे अलग से परामर्श के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इन हितधारकों में से एक ने आगे प्रस्तुत किया है कि किसी भी विलय को CCI द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद स्पेक्ट्रम और बाजार हिस्सेदारी (ग्राहक और राजस्व दोनों) कैप से संबंधित खंड होते हैं;तो इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा ध्यान दिया जाता है।

2.76 एक हितधारक ने प्रस्तुत किया कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र एक एकाधिकार बाजार की ओर बढ़ रहा है, यह ग्राहकों के साथ-साथ सरकार के लिए भी सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। TRAI और दूरसंचार विभाग मौजूदा M&A दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और MNOs को प्रतिस्पर्धा और भारत में दूरसंचार उद्योग के समग्र स्वास्थ्य के लिए VNOs तक पहुँच प्रदान करने के लिए शासनादेश देने पर विचार कर सकते हैं।

विश्लेषण

2.77 UL (VNO) प्रदान करता है कि NSO के लिए अपने VNO के लिए समयबद्ध पहुँच प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि, यह एक NSO और VNO के बीच आपसी समझौते पर छोड़ दिया जाएगा।

2.78 TSPs के पास हमेशा VNO के साथ संलग्न होने का विकल्प होता है, जिसमें उन मामलों को भी शामिल किया जाता है जहां प्रस्तावित विलय 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी से अधिक हो सकता है। भारत में, नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (NSO) और VNO के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था को विनियमित नहीं किया जाता है और MVNO के ग्राहकों को संबंधित मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर (MNO) के समान सेवा की गुणवत्ता होने की संभावना है। हालांकि, MVNO तक पहुंच एक तरीका हो सकता है, जिसके उपयोग से

MNO अपना बाजार हिस्सा निकाल सकता है। इसके अलावा, VNOs के लिए केवल अनिवार्य उपयोग NSO और VNO के बीच थोक मूल्यों को विनियमित नहीं किया जाता है।

2.79 प्राधिकरण का विचार है कि M&A दिशानिर्देशों के भाग के रूप में, TSPs को VNO तक पहुँच देने के लिए आदेश देना उचित नहीं होगा।

D. हितधारकों से प्राप्त अन्य टिप्पणियाँ

2.80 कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि यदि किसी VNO को पहले से ही हस्तांतरकर्ता कंपनी का अभिभावकत्व दिया गया था,तो विलय के बाद, स्थानान्तरी कंपनी को इस तरह के समझौते का सम्मान करना चाहिए।

2.81 हितधारकों में से एक ने प्रस्तुत किया है कि हस्तांतरण / विलय दिशानिर्देशों को एक UL(VNO) के विलय /डीमर्जर के लिए भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लाइसेंस समझौते के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

विश्लेषण

2.82 यह समझा जाता है कि एक बार एक कंपनी / लाइसेंसधारी का विलय होता है या दूसरे में स्थानांतरित होता है, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को भी अधिग्रहण करने वाली कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें स्थानांतरण कंपनी द्वारा दर्ज किए गए समझौतों का सम्मान शामिल होगा। इसलिए, इसके लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

2.83 इसके अलावा, हितधारकों में से एक ने अनुरोध किया कि UL(VNO) के लिए भी दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। प्राधिकरण का विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे की अलग से जाँच की जा सकती है।

E. अन्य मुद्दे

2.84 हालांकि लाइसेंस के स्थानांतरण/विलय के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है, यह उचित हो सकता है कि लाइसेंस में संबंधित खंड की भी जांच की जाए। सामान्य शर्तों पर अध्याय- I में "लाइसेंस के हस्तांतरण पर प्रतिबंध" के तहत एकीकृत लाइसेंस में प्रासंगिक धाराएँ निम्नलिखित हैं:

"6.3 अन्तःसेवा क्षेत्र के विलय और अधिग्रहण के साथ-साथ लाइसेंस का हस्तांतरण

लाइसेंसधारक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

6.4 इसके अलावा, लाइसेंसधारी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाइसेंसर की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ लाइसेंस समझौते को स्थानांतरित या सौंप सकता है, और यदि अन्यथा, प्रतिस्पर्धा में कोई समझौता दूरसंचार सेवाओं के प्रावधानों में नहीं होता है: -

(i) (a) यदि त्रिपक्षीय अनुबंध की प्रक्रियाओं को पूरा करने पर नियम और शर्तों के अनुसार स्थानांतरण या सौंपने का अनुरोध किया जाता है, अगर पहले से ही लाइसेंसर, लाइसेंसधारी और उधारदाताओं के बीच निष्पादित किया जाता है; या

(i) (b) जब भी समामेलन या पुनर्गठन यानी विलय या डीमर्जर को प्रचलित कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया जाता है; प्रावधानों के अनुसार; अधिक विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 तक द्वारा; बशर्ते कि समामेलन या पुनर्गठन की योजना इस तरह से बनाई गई है कि यह लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए लाइसेंसकर्ता की लिखित स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगी, और

(ii) समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंसों के स्थानांतरण या विलय के लिए लाइसेंसकर्ता की पूर्व लिखित सहमति / अनापत्ति प्राप्त की गई है। इसके अलावा, हस्तानान्तरी / समनुदेशिती पात्रता मानदंड के अनुसार पूरी तरह से पात्र है, जो उस क्षेत्र में नए लाइसेंस देने के लिए लागू है और लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए लिखित रूप में अपनी इच्छा दिखाते हैं, जिसमें पिछले और भविष्य के दायित्वों को भी शामिल किया गया है साथ ही जैसा कि लागू हो, शुल्क के हस्तांतरण सहित लाइसेंस / विलय के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना; और

(ii) सभी पिछले बकाया पूरी तरह से हस्तांतरकर्ता कंपनी और स्थानान्तरी कंपनी द्वारा हस्तांतरण / सौंपने की तारीख तक भुगतान किए जाते हैं; और उसके बाद स्थानान्तरी कंपनी भविष्य के सभी बकाया राशि के भुगतान करने का वचन देती है, जो कि आउटगोइंग कंपनी द्वारा पिछले अवधि के भुगतान के बिना बकाया है। "

2.85 हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी टिप्पणी प्रदान करें कि UL के प्रासंगिक प्रावधानों में क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ

2.86 हितधारकों से कोई टिप्पणियाँ नहीं मिली है।

विश्लेषण

2.87 हितधारकों ने उपरोक्त खंडों में किए जाने वाले किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं दिया है। प्राधिकरण को भी यह लगता है कि इन खंडों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय- III: सिफारिशों का सारांश

3.1 प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि:

a) न्यायाधिकरण / कंपनी न्यायाधीश (M&A दिशानिर्देशों का खंड 3(b)) के अनुमोदन के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के एक वर्ष की गणना के लिए अर्थात हस्तांतरण/विलय के लिए अनुमत समय अवधि के लिए, किसी भी दायित्व को आगे बढ़ाने में बिताया गया समय जिस खाते के विलय की अंतिम मंजूरी में देरी हो रही है, उसे बाहर रखा जाना चाहिए।

b) M&A दिशानिर्देशों के खंड 3 (c) का दूसरा भाग, जो लाइसेंसर द्वारा विस्तारित एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग खंड से छूट प्रदान करता है, को इस तरह संशोधित किया जाना चाहिए कि इससे छूट पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग खंड केवल तब तक के लिए प्रदान किया जाता है जब तक लाइसेंस का हस्तांतरण / विलय लाइसेंसधारी द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

c) दिशा-निर्देशों के खंड 3 (c) का अंतिम वाक्य, जो प्रदान करता है कि ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश की मंजूरी के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लिखित में कारण दर्ज करके लाइसेंसकर्ता को उचित रूप से खंड 3 (b) के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि यह समयरेखा को परिभाषित करता है।

[पैरा 2.21]

3.2 प्राधिकरण की सिफारिश है कि संबंधित बाजार में एक NSO की बाजार हिस्सेदारी की गणना करने के लिए, इसके साथ VNO (s) के बाजार में हिस्सेदारी को NSO के बाजार हिस्सेदारी में जोड़ा जाना चाहिए, यदि NSO, VNO का प्रमोटर है। एक प्रमोटर की परिभाषा लाइसेंस में लाइसेंस / दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगी।

[पैरा 2.34]

3.3 प्राधिकरण का सुझाव है कि दिशानिर्देशों के खंड 3 (h) में इस तरह संशोधन किया जा सकता है:

(a) पहुँच, इंटरनेट, VSAT, GMPCS, PMRTS, और INSAT MSS-R सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण के लिए बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए, ग्राहकों की संख्या और साथ ही AGR दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

(b) सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण के बाकी हिस्सों के लिए बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण

करने के लिए यानी NLD, ILD और IPLC के पुनर्विक्रय के लिए, केवल AGR पर विचार किया जाना चाहिए।

[पैरा 2.38]

3.4 प्राधिकरण की सिफारिश है कि यह स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों में उल्लेख किया जाना चाहिए कि परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम के लिए बाजार निर्धारित मूल्य के भुगतान पर, इस तरह के स्पेक्ट्रम को उदारीकृत यानी प्रौद्योगिकी तटस्थ के रूप में माना जाएगा।

[पैरा 2.43]

3.5 प्राधिकरण अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराता है कि यदि कोई हस्तांतरणकर्ता कंपनी स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा रखती है, जिसे भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के बदले सौंपा गया है, तो हस्तांतरी कंपनी / परिणामी इकाई को प्रवेश शुल्क के बदले आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय की लिखित स्वीकृति की तारीख से अंतर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।हालांकि, अंतर राशि के भुगतान की मांग को बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग NCLT अनुमोदन की तारीख से अस्थायी मांग की गणना करेगा, और विलय की मंजूरी मिलने पर, अनुमोदन राशि के अनुमोदन की तारीख के आधार पर अंतर राशि की वास्तविक मांग की पुनर्गणना की जाएगी। हस्तांतरी कंपनी / परिणामी इकाई द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, हस्तांतरी कंपनी / परिणामी संस्था को वापस कर दी जाएगी या अन्य देय राशि के विरुद्ध निपटान कर दी जाएगी।

[पैरा 2.45]

3.6 प्राधिकरण का सुझाव है कि खंड 3 के अंतिम वाक्य में (i) "हस्तांतरी (यानी अधिग्रहण करने वाली कंपनी)" को "हस्तांतरणकर्ता कंपनी (यानी अधिग्रहित कंपनी)" से बदल दिया जाना चाहिए।

[पैरा 2.48]

3.7 प्राधिकरण का सुझाव है कि लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय पर दिशानिर्देश स्पेक्ट्रम कैप को हार्ड-कोड नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, इसे लाइसेंस के संबंधित खंड के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

[पैरा 2.58]

अनुलग्नक 1.1

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
एक्सेस सर्विसेज विंग

संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 संख्या: 20-281/2010-AS-I

Vol. XII (pt.) दिनांक:08.05.2019

सेवा में,
सचिव,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ओल्ड मिंटो रोड,
नई दिल्ली -110002

विषय: राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की रणनीतियों पर TRAI की सिफारिशों की मांग के विषय में,

भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (इसके बाद, NDCP, 2018 के रूप में संदर्भित), 'कनेक्ट इंडिया' और 'प्रोपेल इंडिया' मिशन के तहत निम्नलिखित रणनीतियों की परिकल्पना करती है।

"

1. कनेक्ट इंडिया: एक ठोस डिजिटल संचार आधारभूत संरचना बनाना

...

रणनीति:

1.1 ***<u>सार्वजनीन ब्रॉडबैंड पहुँच के लिए एक 'नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान' की स्थापना</u>***

(j) पुनर्विक्रय और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (VNO) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण और पहुंच सहित नवीन दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना

2. प्रोपेल इंडिया: निवेश, नवाचार, स्वदेशी निर्माण और I PR निर्माण के जरिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और सेवाओं को सक्षम बनाना

Strategies:

2.1 ***<u>डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए निवेश को उत्प्रेरित करना:</u>***

(b) *निम्न के द्वारा निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्था को सुधारना, और आसानी से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना:*

v. विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों (जैसे बुनियादी ढाँचा, नेटवर्क, सेवाएँ और अनुप्रयोग स्तर) की असंबद्धता को सक्षम करना

(c) *निम्न के द्वारा दायित्व अनुपालन को सरल और सुगम बनाना:*

v. विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देशों,2014 में सुधार के माध्यम से अनुमोदन के सरलीकरण और तेज ट्रैकिंग को सक्षम करना

viii. वन नेशन-वन नंबर की सुविधा के लिए निश्चित संख्या के पोर्टेबिलिटी के लिए एक व्यवस्था बनाना - जिसमें टोल फ्री नंबर की पोर्टेबिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर और DID नंबर शामिल हैं

2.2 ***उपयोग के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना***
<u>उभरती तकनीकी</u>

(e) इनके द्वारा *पर्याप्त संख्या में संसाधन सुनिश्चित करना*

ii. फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग योजना विकसित करना

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997(यथा संशोधित) की धारा 11 के उप-धारा (1) के खंड (a) की शर्तों के तहत NDCP, 2018 के पूर्वोक्त मदों में से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है।

3. सुविधा के लिए, NDCP, 2018 की रणनीतियों के तहत रणनीतियों / मदों, जिन पर TRAI की सिफारिश मांगी जा रही है, नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(a) 'कनेक्ट इंडिया' मिशन की रणनीति 1.1 (j),

(b) मद (v) रणनीति 2.1 (b) के तहत 'प्रोपेल इंडिया' मिशन,

(c) आइटम (v) और (viii) रणनीति 2.1 (c)'प्रोपेल इंडिया' मिशन के तहत, और

(d) आइटम (ii) 'प्रोपेल इंडिया' मिशन की रणनीति 2.2 (e) के तहत।

यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव के अनुमोदन से जारी होता है।

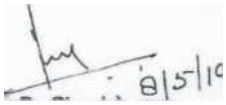

(

(एस.बी. सिंह)
उप महानिदेशक (AS)
टेली.: 011-23036918

अनुलग्नक 1.2

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
एक्सेस सर्विसेज विंग

संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 संख्या -: 20-281/2010-

AS-I Vol. XII (pt.) दिनांक: 11.06.2019

सेवा में,

सचिव,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ओल्ड मिंटो रोड,
नई दिल्ली -110002

विषय: राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018- की रणनीतियों पर TRAI की सिफारिशों की मांग करते हुए दूरसंचार विभाग के दिनांक 08.05.2019 के पत्र के संबंध में निविष्टियां - के संबंध में,

यह दिनांक 08.05.2019 के पत्र के संदर्भ में है, जिसके माध्यम से दूरसंचार विभाग (DoT) ने TRAI से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के उप-धारा (1) के खंड (a) की शर्तों के तहत ,NDCP, 2018 की कुछ रणनीतियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। दूरसंचार विभाग के दिनांक 08.05.2019 के पत्र की एक प्रति अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न है।

2. इस संबंध में,आपका ध्यान प्रोपेल इंडिया मिशन '(अर्थात 'विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश,2014 में पुन: निर्धारण, अनुमोदन के सरलीकरण और तेजी से ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए सुधार)रणनीति 2.1 (c) के तहत मद (v) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो मदों में से एक है, जिस पर दूरसंचार विभाग ने 08.05.2019 के पत्र के माध्यम से TRAI की सिफारिशें मांगी हैं।

3.
उपर्युक्त मद के संदर्भ में, यह कहा गया है कि, पहले, दूरसंचार विभाग ने कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन पर यूनिफाइड लाइसेंस FULl के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के लिए पत्र संख्या 20-281 / 2010-AS-l (वॉल्यूम- VII) दिनांक 20.02.2014 के माध्यम से दिशानिर्देश (बाद में 'विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश, 2014 ^, के रूप में संदर्भित) जारी किए।

विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति, 2014 को अनुलग्नक- IX के रूप में रखी गयी है। इन दिशानिर्देशों को पत्र संख्या 20-281 / 2010-AS-l (वॉल्यूम- VII) दिनांक 30.05.2018 **(अनुलग्नक- III)** और 20-281 / 2010-AS-l (वॉल्यूम- VII) दिनांक 24.09.2018 **(अनुलग्नक- IV)** के माध्यम से संशोधित किया गया था। । दूरसंचार विभाग ने पिछले पांच वर्षों में विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश,2014 के प्रावधानों के आलोक में लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए कई प्रस्तावों की जांच की है।

4. लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए किसी भी प्रस्ताव की जांच करने के बाद, दूरसंचार विभाग, विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश, 2014 के प्रावधानों के आधार पर लागू शर्तों को पूरा करने के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति को हस्तांतरण / विलय को रिकॉर्ड पर ले जाने की सूचना देता है। अतीत में कई उदाहरणों में, विलय करने वाली संस्थाओं ने माननीय TDSAT के समक्ष इस प्रार्थना की याचिका दायर की है और दूरसंचार विभाग द्वारा अन्य बातों के साथ विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश,2014 के अनुच्छेद 3 (i) और के 3 (m) के रूप में उन पर लगाई गई कुछ शर्तों को अलग और समाप्त करने का निवेदन किया है। माननीय TDSAT, ने कई मौकों पर, ऐसी कुछ शर्तों के संचालन के स्थगन की अनुमति दी है।

5. आपका ध्यान वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (VNOAI) से प्राप्त प्रतिनिधित्व की प्रति पत्रांक VNOAI/11/2018 दिनांक 16.11.2018 **(अनुलग्नक- V)** पर भी आकृष्ट किया जाता है। अपने पत्र में, VNOAI ने, अन्य बातों के साथ, ने एकाधिकार से बचाव और विलय किए गए संस्थाओं पर MVNOs / VNOs को अनिवार्य करके प्रतियोगिता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का विवरण प्रदान किया है।

6. उपर्युक्त आदानों पर 'सरलीकरण और अनुमोदन की तेजी से निगरानी को सक्षम करने के लिए विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश,2014 में सुधार' पर सिफारिशें प्रदान करते हुए विचार किया जा सकता है।

7. यह सचिव,दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी होता है।

संलग्नक: यथोपरि

(एस.बी.सिंह) [1]
DDG (AS)
टेलीफोन: 011-2303 6918

भारत सरकार
सूचना एवं संचार तकनीकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन /20, अशोक रोड, 'नई दिल्ली
(AS- I डिवीजन)

संख्या.20-281/2010-AS-! (Volume-VII) दिनांक: 20 फरवरी, 2014

विषय: कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन पर एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणियों के स्थानांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देश.

1. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -2012 में दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सरलीकृत विलय और अधिग्रहण व्यवस्था को लागू करने की रणनीति की परिकल्पना की गई है। 100% FDI की अनुमति देकर इस क्षेत्र को और उदार बनाया गया है। इसके अलावा, स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति देने के लिए अप्रभावी निर्णय लिया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 में भी कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा संशोधन किया गया है और कंपनियों के समझौता / व्यवस्था और समामेलन के संदर्भ में संशोधन किए गए हैं। SEBI ने IPO के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन की योजना समय-समय पर संशोधित की गई। इस तरह की योजनाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून / न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। नतीजतन, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न लाइसेंस ऐसी कंपनियों को परिणामी संस्था(संस्थाओं) को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि इस तरह की योजनाओं में कंपनी के अवशोषण या व्यवस्था या समामेलन आदि द्वारा गठन या विलय के बाद विलय शामिल हो सकता है और उसके बाद इस तरह के लाइसेंस / प्राधिकरण को विलय / स्थानांतरित कर सकता है जो इस शर्त के अधीन है कि परिणामी इकाई समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में ऐसे लाइसेंस / प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. इससे पहले विभाग ने इंट्रा सर्विस एरिया मर्जर ऑफ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज (CMTS) / यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज (UAS) लाइसेंस के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या.20-232 / 2004-BS-III दिनांक 22 अप्रैल 2008 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और TRAI की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11.05.2010 और 03.11.2011 और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012, इन दिशानिर्देशों के अधिमूल्यन में, यह आगे निर्णय लिया गया है कि UL के तहत दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के स्थानांतरण / विलय को टेलीग्राफ और दूरसंचार सेवाओं के उचित संचालन के लिए नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जिससे आम जनता और विशेष रूप से उपभोक्ता हित में सेवा प्रदान की जा सकती है: -

a) ट्रिब्यूनल या कंपनी न्यायाधीश के समक्ष दायर कंपनियों के समझौते, व्यवस्था और समामेलन के किसी भी प्रस्ताव के लिए लाइसेंसकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस योजना पर लाइसेंसधारक द्वारा आगे, प्रतिनिधित्व / आपत्ति, यदि कोई हो, तो इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी संबंधितों को बनाना और सूचित करना होगा।

b) ट्रिब्यूनल / कंपनी न्यायाधीश द्वारा इस तरह की योजना की उपयुक्त स्वीकृति के बाद ऐसे मामलों में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न लाइसेंसों के हस्तांतरण / विलय के लिए एक वर्ष की समय अवधि की अनुमति दी जाएगी।

c) यदि कोई लाइसेंसधारी किसी नीलामी में भाग लेता है और परिणामस्वरूप लॉक-इन स्थिति के अधीन है, तो यदि ऐसा कोई लाइसेंसधारी लागू होने वाली कंपनियों के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य लाइसेंसधारी में विलय / समझौता / व्यवस्था / संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, तो लॉक-इन अवधि नए शेयरों के संबंध में लागू होगी जो परिणामी कंपनी {हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के संबंध में जारी की जाएगी। पर्याप्त इक्विटी / क्रॉस होल्डिंग क्लॉज एक वर्ष की इस अवधि के दौरान लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्यथा नहीं बढ़ाया जाए। यह अवधि लाइसेंसधारक द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाई जा सकती है।

d) लाइसेंस / प्राधिकरण का विलय संबंधित सेवा श्रेणी के लिए होगा। चूंकि एक्सेस सर्विस लाइसेंस / प्राधिकरण इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान की अनुमति देता है, ISP लाइसेंस / प्राधिकरण का एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस/प्राधिकरण के साथ विलय की भी अनुमति दी जाएगी,

e) हस्तांतरी (अधिग्रही) कंपनी को हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी द्वारा आयोजित परिसंपत्तियों / आयतों / प्राधिकरण के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी के लाइसेंस / प्राधिकरण परिणामी इकाई में रखे जाएंगे। परिणामस्वरूप, विभिन्न लाइसेंसों / प्राधिकरणों की वैधता की तारीख लाइसेंस / प्राधिकरण के अनुसार होगी और उस सेवा के लिए लाइसेंस / प्राधिकरण की विस्तारित अवधि के लिए, यदि कोई हो, तो भुगतान के अधीन विलय की तारीख को दो अवधियों के उच्चतर के बराबर होगा। हालाँकि, हस्तांतरणकर्ता (अधिग्रहित) कंपनी द्वारा रखे गए परिसंपत्ति / लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण के बाद स्पेक्ट्रम की वैधता अवधि अपरिवर्तित रहेगी।

f) किसी भी अतिरिक्त सेवा या किसी भी लाइसेंस क्षेत्र / सेवा क्षेत्र के लिए, संबंधित प्राधिकरण के साथ एकीकृत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

g) एक्सेस सेवाओं के लिए एक बैंड में 50% के स्पेक्ट्रम कैप को ध्यान में रखते हुए, समझौता करने के लिए लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के परिणामस्वरूप, कंपनियों की व्यवस्था या समामेलन की अनुमति दी जाएगी जहां परिणामी इकाई के संबंधित सेवा क्षेत्र में पहुंच सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी 50% से ऊपर है । विलय या अधिग्रहण या समामेलन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किसी भी सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी में परिणाम 50% से अधिक हो जाता है, परिणामी संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय या अधिग्रहण या समामेलन के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% की सीमा तक कम करना चाहिए । यदि परिणामी निकाय एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक कम करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसकर्ता द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

h) उपरोक्त बाजार में हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए, सब्सक्राइबर बेस और संबंधित बाजार में लाइसेंसधारी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) दोनों के बाजार हिस्सेदारी पर विचार किया जाएगा। संपूर्ण एक्सेस मार्केट मार्केट शेयर का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक बाजार होगा जिसमें वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस सब्सक्राइबर भी शामिल होंगे। एक्सचेंज डेटा रिकॉर्ड्स (EDR) का उपयोग वायरलाइन ग्राहकों की गणना और ग्राहक आधार के आधार पर कंप्यूटिंग बाजार हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिए वायरलेस ग्राहकों की गणना में विज़िटर लोकेशन रजिस्टर (VLR) डेटा या समतुल्य की गणना में किया जाएगा। EDRA/LR डेटा के समतुल्य लेने की संदर्भ तिथि आवेदन की तिथि के आधार पर प्रत्येक वर्ष की 31

दिसंबर या 30 जून होगी। विधिवत अंकेक्षित एजीआर संबंधित बाजार में ऑपरेटरों के लिए राजस्व आधारित बाजार हिस्सेदारी की गणना का आधार होगा। AGR की विधिवत लेखा परीक्षा की तारीख पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च होगी।

t) यदि एक हस्तांतरकर्ता (अधिग्रहीत) कंपनी स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा रखती है, जो (4.4 मेगाहर्ट्ज / 2.5 मेगाहर्ट्ज) को प्रवेश शुल्क के एवज में सौंपा गया है, तो हस्तांतरी (अधिग्रहण करने वाली) कंपनी (अर्थात परिणामी विलय इकाई), विलय के समय सरकार को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल /कंपनी न्यायाधीश द्वारा ऐसी व्यवस्था के अनुमोदन की तारीख से स्पेक्ट्रम की निर्धारित कीमत लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुपात के आधार पर प्रवेश शुल्क और बाजार के बीच निर्धारित अंतर का भुगतान करेगी। वर्ष 2010 के बाद से आयोजित नीलामी के माध्यम से अधिग्रहित स्पेक्ट्रम के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी निर्धारित मूल्य एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, उसके बाद, भारतीय स्टेट बैंक दरों पर PLR को एक वर्ष की अवधि के बाद बाजार निर्धारित मूल्य पर पहुंचने के लिए अंतिम नीलामी निर्धारित मूल्य में जोड़ा जाएगा। हस्तांतरी (यानी अधिग्रहण करने वाली इकाई) कंपनी, बैंक के संबंध में विलय से पहले CDMA बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज और GSM बैंड में 4.4 मेगाहर्टज से अधिक स्पेक्ट्रम होल्डिंग के संबंध में एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए उठाए गए मांगों के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति में एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए विभाग द्वारा उठाए गए मांग के बराबर राशि की गारंटी कोर्ट केस के अंतिम परिणाम को प्रस्तुत करेगी।

j) स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज (SUC) जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, परिणामी इकाई के कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर भी देय होगा।

k) परिणामस्वरूप, सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के लिए समझौता, व्यवस्था या संशोधन और लाइसेंस के विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम पहुंच सेवाओं के लिए सौंपे गये कुल स्पेक्ट्रम का 25% और किसी दिए गए बैंड में, नीलामी के द्वारा या अन्यथा संबंधित सेवा क्षेत्र में सौंपा गए स्पेक्ट्रम का 50% से अधिक नहीं होगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित NIAs में इस तरह की कैप के लिए बैंड की गिनती की जाएगी। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में, उपरी सीमा 10 मेगाहर्ट्ज होगी। इसके अलावा, उस स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित प्रासंगिक शर्तें लागू होंगी। भविष्य की नीलामी के मामले में, इस तरह की नीलामी के लिए निर्धारित प्रासंगिक शर्तें लागू होंगी। हालाँकि, 2010 में 3G/BWA स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित नीलामी के माध्यम से हस्तान्तरणकर्ता और हस्तांतरी कंपनी को 3 जी स्पेक्ट्रम का एक ब्लॉक आवंटित किया गया था, परिणामी इकाई भी संबंधित सेवा क्षेत्रों में 3 जी स्पेक्ट्रम के दो ब्लॉकों को बनाए रखने के लिए अनुमति होगी। कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन का परिणाम और एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय, स्पेक्ट्रम बैंड कैप के 50% के भीतर होना।

I) यदि, विलय के परिणामस्वरूप, प्रासंगिक इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से परे है, तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। परिणामी निकाय के कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क इस तरह की अवधि के लिए लगाया जाएगा, यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम एक वर्ष के भीतर मर्ज किए गए इकाई द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो संबंधित लाइसेंस के तहत ऐसे मामलों में अलग से कार्रवाई की जाएगी। / वैधानिक प्रावधान, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के गैर-आत्मसमर्पण के लिए सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। हालाँकि, अधिक स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए और / या देय पैसे का कोई भी वापसी या सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।

m) विलय की संस्थाओं के लाइसेंस से संबंधित सभी मांगों, यदि कोई हो, तो लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय / हस्तांतरण की अनुमति जारी करने से पहले दोनों लाइसेंसधारियों में से किसी एक को मंजूरी देनी होगी। यह किसी लंबित कानूनी मामलों या विवादों के बावजूद कंपनी द्वारा दायर रिटर्न के आधार पर सरकार / लाइसेंसकर्ता द्वारा की गई मांग के अनुसार होगा। परिणामी इकाई द्वारा इस आशय की एक प्रविष्टि प्रस्तुत की जाएगी कि हस्तांतरी या हस्तांतरकर्ता कंपनी के पूर्व-विलय अवधि के लिए किसी भी मांग का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, विधिक न्यायालय द्वारा हस्तांतरी या हस्तांतरकर्ता कंपनी के एक बार के

स्पेक्ट्रम शुल्क को छोड़कर अन्य मांगों को इस तरह के मुकदमेबाजी के निर्णय के परिणाम के अधीन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के ऊपर पैरा 3 (i) में प्रावधानों के अनुसार एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क देय होगा।

n) यदि किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंस के हस्तांतरण / 'विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई एक "सिग्नीफिकेंट मार्केट पावर" (SMP) बन जाती है, तो SMP पर लागू होने वाले मौजूदा नियम और नियम भी परिणामी इकाई के लिए लागू होंगे। *एक्सेस सेवाओं के संबंध में SMP को TRAI के "द टेलीकॉम इंटरकनेक्ट (रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर) विनियम, 2002 (2002 का 2)" के रूप में समय-समय पर संशोधित किया जाता है।*

3. विवाद समाधान दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ समय-समय पर संशोधित TRAI अधिनियम 1997 के अनुसार होगा।

4. लाइसेंसकर्ता के पास इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने या राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित के हित में और टेलीग्राफ के उचित संचालन के लिए आवश्यक नए दिशानिर्देशों को शामिल करने का अधिकार है।

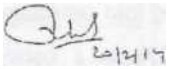

(आर के सोनी) निदेशक (AS-I)
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए
Ph.23036284

Annexure-IH

संख्या.: 20-281/2010-AS-I (Vol. VII)

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

एक्सेस सर्विसेज विंग

संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली,दिनांकित, 30.05.2018

विषय: दिनांक 20.02.2014 से कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन पर एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत विभिन्न श्रेणियों के सेवा हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन।

'कंपनियों के हस्तांतरण, व्यवस्था और एकीकरण पर एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के दिशानिर्देश' (5) के अनुसरण में, (बाद में, विलय और अधिग्रहण के दिशानिर्देश, 2014 के रूप में संदर्भित) दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 20.02.2014 को जारी किए गए अधिग्रहण दिशानिर्देश, 2014 और उसके बाद स्पेक्ट्रम रखने के लिए कैप की सीमा में संशोधन, दूरसंचार विभाग इसके द्वारा विलय और अधिग्रहण के दिशानिर्देश, 2014 के खंड (3), के उप-खंड (g) और उप-खंड (k) में नीचे दिए गए विवरण के रूप में संशोधन करता है। :

वर्तमान खंड	संशोधित खंड
g) एक्सेस सेवाओं के लिए एक बैंड में 50% के स्पेक्ट्रम कैप को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों के समझौते, व्यवस्था या समामेलन के परिणामस्वरूप लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय की अनुमति दी जाएगी, जहां परिणामी इकाई के संबंधित सेवा क्षेत्र में पहुंच सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी 50% तक है। विलय या अधिग्रहण या समामेलन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किसी भी सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी में परिणाम 50% से अधिक हो जाता है,तो	g) कंपनियों के समझौता, व्यवस्था या समामेलन के फलस्वरूप लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय की अनुमति दी जाएगी, जहां परिणामी इकाई के संबंधित सेवा क्षेत्र में पहुंच सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी 50% तक है। विलय या अधिग्रहण या समामेलन प्रस्तावों के कारण किसी भी सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी में परिणाम 50% से अधिक हो जाता है,तो

30/05/18

परिणामी संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय या अधिग्रहण या समामेलन के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% की सीमा तक कम करना चाहिए , यदि परिणामी इकाई एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक कम करने में विफल रहती है, तो लाइसेंसकर्ता द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।	परिणामी संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय या अधिग्रहण या समामेलन के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक सीमित कर देना चाहिए । यदि परिणामी इकाई एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी बाजार हिस्सेदारी 50% की सीमा तक कम करने में विफल रहती है, तो लाइसेंसकर्ता द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
k) परिणामस्वरूप किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के समझौते, व्यवस्था या समामेलन और विलय की योजना के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम पहुंच सेवाओं के संबंधित सेवा क्षेत्र में लिए , सौंपे गए कुल स्पेक्ट्रम का 25% और किसी सौंपे गये बैंड में, नीलामी के माध्यम से या अन्यथा स्पेक्ट्रम के 50% से अधिक नहीं होगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित NIAs में इस तरह के कैप के लिए बैंड की गणना की जाएगी। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में, उपरी सीमा 10 मेगाहर्ट्ज होगी। इसके अलावा, उस स्पेक्ट्रम के नीलामी से संबंधित प्रासंगिक शर्तें लागू होंगी। भविष्य की नीलामी के मामले में, इस तरह की नीलामी के लिए निर्धारित प्रासंगिक शर्तें लागू होंगी। हालाँकि, अगर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी कंपनी को 2010 में 3GIBWA स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित नीलामी के माध्यम से 3 जी स्पेक्ट्रम का एक ब्लॉक आवंटित किया गया था, परिणामी इकाई को संबंधित सेवा क्षेत्रों में 3 जी स्पेक्ट्रम के दो ब्लॉक को कंपनियों के समझौता, व्यवस्था और समामेलन के परिणामस्वरूप और एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय बनाए रखने की,स्पेक्ट्रम बैंड कैप के 50% के भीतर, अनुमति होगी।	k) समझौता, व्यवस्था या समामेलन और एक सेवा क्षेत्र में लाइसेंस के विलय की योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम कैप के संबंध में निम्नलिखित शर्तें परिणामी इकाई पर लागू होंगी। (i) (i) परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में, नीलामी के माध्यम से या अन्यथा पहुंच सेवाओं के लिए निर्दिष्ट कुल स्पेक्ट्रम का 35% से अधिक नहीं होगा। (ii) परिणामी निकाय द्वारा उप -1 गीगाहर्ट्ज बैंड (700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड) में संबंधित सेवा क्षेत्र में नीलामी द्वारा या अन्यथा,संयुक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग सब -1 गीगाहर्ट्ज बैंड में सौंपे गए कुल स्पेक्ट्रम के 50% से अधिक नहीं होगी। (iii) स्पेक्ट्रम कैप की गणना के लिए अगस्त 2016 के NIA में लागू किए गए सिद्धांतों को संशोधित किए जाने के साथ-साथ सब-1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कैप की गणना करते समय भी लागू किया जाएगा।

	यदि केस हस्तान्तरणकर्ता और हस्तांतरी कंपनी को 2010 में 3 जी / BWA स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित नीलामी के माध्यम से 3 जी स्पेक्ट्रम (2100 मेगाहर्ट्ज) का एक ब्लॉक आवंटित किया गया था, तो परिणामी इकाई को संबंधित सेवा क्षेत्रों में उपरोक्त उल्लिखित नीलामी, कंपनियों के एकीकरण और व्यवस्था और एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के परिणामस्वरूप 3 जी स्पेक्ट्रम (2100 मेगाहर्ट्ज) के दो ब्लॉकों को बनाए रखने की अनुमति होगी।

2. विलय और अधिग्रहण दिशानिर्देश, 2014 में उपर्युक्त संशोधन तुरंत प्रभाव में आ जाएंगे। (नंद किशोर बिजरानियाँ)

ए डी जी (AS-V)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और
उनके लिए टेलीफोन: 011-23036416

30/05/18

सेवा में,
निदेशक (आईटी) को दूरसंचार विभाग की वेब-साइट पर प्रकाशन के लिए

To,

A Annexure - IV

-

संख्या : 20-281/2010-AS-I (Vol. VU)

संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
एक्सेस सर्विसेज विंग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24.09.2018

विषय: कंपनियों के दिनांक 20.02.2014 के समझौता, व्यवस्था और समामेलन पर एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस / प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देश।

दूरसंचार सेवा के विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देश (5) के अनुपालन में, एकीकृत लाइसेंस (UL) के तहत प्राधिकरण के समझौते, व्यवस्था और कंपनियों के दिनांक 20.02.2014 के समामेलन के तहत प्राधिकरण (इसके बाद, "विलय और अधिग्रहण दिशानिर्देश, 2014" के रूप में, संदर्भित) दूरसंचार विभाग, इसके द्वारा, विलय और अधिग्रहण के दिशानिर्देश, 2014 के खंड (3) के उप-खंड (a) और उप-खंड (I) में नीचे वर्णित अनुसार संशोधन करता है। :

वर्तमान खंड	संशोधित खंड
a) ट्राइब्यूनल या कंपनी न्यायाधीश के समक्ष दायर कंपनियों के समझौते, व्यवस्था और समामेलन के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए लाइसेंसकर्ता को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी योजना पर लाइसेंसर द्वारा यदि कोई हो, तो प्रतिनिधित्व / आपत्ति, यदि कोई हो, तो सभी संबंधितों को इस तरह के नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।	a) ट्रिब्यूनल या कंपनी जज के सामने दायर किए गए समझौते के अनुसार किसी भी प्रस्ताव के लिए लाइसेंसधारी को सूचित किया जाएगा। आगे, प्रतिनिधित्व / आपत्ति, यदि कोई हो, तो लाइसेंसधारक द्वारा ऐसी योजना पर और एकीकृत लाइसेंस के तहत लाइसेंस / प्राधिकरण के विलय / हस्तांतरण पर, इस तरह के नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी संबंधितों को बनाया और सूचित किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल / कंपनी जज द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, लाइसेंसकर्ता यूनिफाइड लाइसेंस के तहत लाइसेंस / प्राधिकरण के हस्तांतरण / विलय को मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित मंजूरी प्रदान करेगा।

I) यदि, विलय के परिणामस्वरूप, प्रासंगिक इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से परे है, तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। परिणामी इकाई के कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क ऐसी अवधि के लिए लगाया जाएगा। यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो, ऐसे मामलों में संबंधित लाइसेंस / वैधानिक प्रावधानों के तहत अलग-अलग कार्रवाई, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के गैर-आत्मसमर्पण के लिए सरकार द्वारा ली जा सकती है। हालांकि, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए और / या देय पैसे का कोई वापसी या सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।	I) यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई द्वारा आयोजित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से परे है, तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण या कारोबार करना होगा। परिणामी इकाई के कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क ऐसी अवधि के लिए लगाया जाएगा। यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम का समर्पण नहीं किया जाता है या | एक वर्ष के भीतर कारोबार किया जाता है, तो ऐसे मामलों में अलग-अलग कार्रवाई, संबंधित लाइसेंस / वैधानिक प्रावधानों के तहत, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के गैर-आत्मसमर्पण / गैर-व्यापार के लिए सरकार द्वारा ली जा सकती है। हालांकि, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए और/या देय पैसे का कोई वापसी या सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।

2. विलय और अधिग्रहण दिशानिर्देश, 2014 में उपर्युक्त संशोधन तुरंत प्रभाव में आ जाएंगे.

(सुजीत कुमार) ए
डी जी (ए एस - V)
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए
टेलीफोन: 011-23036416

सेवा में,

निदेशक (आईटी), दूरसंचार विभाग-मुख्यालय, नई दिल्ली को दूरसंचार विभाग के वेब-साइट पर प्रकाशन के लिए

Ref: VNOAi/11/2018 दिनांक:46.11.2018

सेवा में,
अध्यक्ष
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-100 002

विषय: कार्टेलाइजेशन से बचने और विलय किए गए संस्थानों के लिए MVNOs/VNOs को अनिवार्य करके प्रतियोगिता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का हाल ही में दो शीर्ष ऑपरेटरों (आइडिया-वोडाफोन) के विलय और भारत में 3 + 1 बाजार के निर्माण का सन्दर्भ।

महोदय/महोदया,

यह हाल ही में दो बड़े ऑपरेटरों (आइडिया-वोडाफोन) के विलय और अधिग्रहण के कारण प्रतिस्पर्धा के कमी के मुद्दे के संदर्भ में है,यह विलय 80,000/- करोड़ रूपयों के राजस्व के साथ मार्केट लीडर भारती एयरटेल को पीछे छोड़ते हुए एक नई इकाई का गठन कर रहा है। हालांकि, वोडाफोन और आइडिया के प्रस्तावित विलय से M&A नीति के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां हैं। नई इकाई का RMS बाजार के समग्र राजस्व का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हमें एक ओर स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग और दूसरी ओर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन की आवश्यकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का मूल उद्देश्य प्रासंगिक बना हुआ है। इस तरह की स्थितियों के मद्देनजर, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों ने सब्सक्राइबर बेस के संदर्भ में बाजार हिस्सेदारी का इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटर के प्रभुत्व को वर्गीकृत करने के मानदंडों में से एक के रूप में किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियामकों और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने विलय को केवल इस प्रतिबद्धता पर स्पष्ट किया है कि मेजबान मर्ज की गई इकाई MVNOs के लिए पूरी बिक्री क्षमता का 20% MBA आधार पर अग्रिम प्रतिबद्धता के साथ अलग कर देगी।.

P 3 6 6
Virtual Network Operators Association of India Registered Office: Vatifca Business Centre, Mazzanine Floor,
New Delhi Airport Express Line station, Konnectus Building, Connaught Place, New Delhi-110001
CIN No: U64200DL2016NPL304974

हम आपको यूरोपीय संघ में उपयोग किए गए कुछ मामले प्रदान करते हैं जहां हाल ही में प्रमुख ऑपरेटरों के बीच कुछ M&A गतिविधि हुई हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और अंतिम उपभोक्ताओं को अच्छे प्रतिस्पर्धी उत्पादों की उपलब्धता के लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों / नियामकों को MVNOs के लिए पूरी बिक्री क्षमता का 20% निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है।

विश्व स्तर पर - ऊपर वर्णित परिदृश्य से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि: -

- ग्राहक TSPs के बीच समेकन (विलय और अधिग्रहण के माध्यम से) के बावजूद पसंद और प्रतिस्पर्धी बाजार के लाभों का आनंद लेना जारी रखें।

जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करना: -

° स्पेक्ट्रम को कुछ जिम्मेदार प्रतियोगियों को आवंटित किया जाता है और कई TSPs के बीच खंडित नहीं किया जाता है

*सम्पूर्ण के रूप में उद्योग के लिए कैपेक्स व्यय को स्थायी स्तर पर रखा गया है (यह सुनिश्चित करना कि बहुत अधिक TSP's निवेश नहीं करें और देश भर में आवश्यकताओं से अधिक प्रतिलिपि अधिसंरचना का निर्माण न करें।

विश्व स्तर पर नियामक अधिकारियों ने M&A के मामले में शासनादेश दिया है कि -

⁰ TSPs जो अन्य TSPs के साथ विलय के लिए चयन कर रहे हैं, या अन्य TSPs प्राप्त करने के लिए MVNOs के अनन्य उपयोग के लिए उनकी स्पेक्ट्रम क्षमता (ऑपरेटर के 'प्रभुत्व' के आधार पर आमतौर पर 20-40%) का एक निश्चित अनुपात आवंटित करना चाहिए।

o इस तरह के TSPs अनिवार्य MVNOs (शायद 1-5 MVNOs) को होस्ट करने के लिए अनिवार्य हैं

⁰ TSPs को MVNOs को 'गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है अर्थात् TSPs को अपने होस्ट किए गए MVNOs के ग्राहकों को सभी सुविधाएं (जैसे कवरेज, 4 जी नेटवर्क तक पहुंच आदि) का विस्तार करना चाहिए, जो कि अपने स्वयं के ग्राहकों को प्रदान करता है।

- कुछ मामलों में, नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने वाले TSP's भी शासनादेश के अधीन हैं, जो MVNO को TSP's के नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

हम प्रस्तुत करते हैं कि भारत में भी इसी तरह की स्थितियां पेश की जा सकती हैं। VNOs का समर्थन करने के लिए भारत में बड़े अवलंबी TSPs को अनिवार्य करना - यह सुनिश्चित करेगा कि कम समय में भारत में कई VNOs उभरेंगे।

VNOs की एक बड़ी संख्या के साथ, 4 बड़े TSPs के साथ सह-विद्यमान है जो समेकन की वर्तमान लहर के बाद उभरेंगे - ग्राहक प्रतिस्पर्धी बाजार के लाभ यानी कम, अधिक किफायती लागत, नवीन सेवाओं और कई की पसंद ब्रांडों का आनंद लेना जारी रखेंगे।

बड़े TSPs का प्रभुत्व - बाजार में मूल्य निर्धारण शक्ति के रूप में व्यक्त की गई, बड़ी संख्या में VNOs की उपलब्धता से पर्दा उठाया जाएगा, जो उपभोक्ताओं के लिए 'वैकल्पिक सेवा प्रदाता' होंगे।

हम प्रस्तुत करते हैं कि विलय और अधिग्रहण के लिए TSPs को दूरसंचार विभाग और TRAI द्वारा इस तरह के अधिदेश लागू किए जाते हैं ताकि अंतिम ग्राहकों को लाभ मिलता रहे।

<u>वैश्विक परिदृश्य और केस स्टडी</u>

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अन्य देशों के नियामकों ने उस देश में TSPs के बीच विलय और अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में MVNOs को थोक नेटवर्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यूरोप में कुछ केस स्टडी निम्नलिखित हैं

1 . ऑस्ट्रिया - Hutchison द्वारा Orange Austria का अधिग्रहण।

Hutchison को आदेशित किया गया था

- सुनिश्चित किया कि अपनी क्षमता का 30% तक अपने थोक व्यापार के लिए समर्पित था।
- अगले दस वर्षों के लिए 16 MVNOs तक थोक पहुंच (अर्थात इसके स्पेक्ट्रम को उपलब्ध कराना) की अनुमति दिया;
- अधिग्रहण को पूरा करने से पहले यूरोपीय आयोग द्वारा कम से कम एक MVNO अनुमोदित के साथ सियान व्होलसेल एक्सेस समझौता।
- http://eurooa.eu/r3oid/press-reiease IP-12-1361 en.htm

2.आयरलैंड- Hutchison और Telefonica के मध्य विलय .

Hutchison was mandated to

- दो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (MVNOs) की उनमें से एक के लिए बाद में एक पूर्ण मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बनने के लिए एक विकल्प के साथ अल्पकालिक प्रविष्टि सुनिश्चित किया। Hutchison ने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के पांच ब्लॉकों को बाद की तारीख में MVNO में विभाजित करने के लिए प्रतिबद्ध किया।
- आयरलैंड में भुगतान किए गए दो MVNOs के लिए विलय की गई कंपनी की नेटवर्क क्षमता का 30% बेचना सुनिश्चित किया। (आमतौर पर "पे-एज़-यू-गो" थोक मूल्य निर्धारण मॉडल के बजाय, आमतौर पर TSPs और MVNOs के बीच उपयोग किया जाता है, जहां MVNOs के ग्राहकों के उपयोग के अनुसार भुगतान किया जाता है।)

- http://eurooa.eu/raDid/Dress-release IP-14-607 en.htm

3.जर्मनी - Telefonica द्वारा E-Plus का अधिग्रहण

Telefonica ने नियामक को नीचे वर्णित प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत कीं -

°. अधिग्रहण पूरा होने से पहले, जर्मनी में एक से तीन MVNOs के लिए विलय की गई कंपनी की क्षमता का 30% तक तय भुगतान पर बेचना।

* 'Telefonica's और E-Plus' के साझेदारों (यानी MVNOs और सेवा प्रदाताओं) के साथ मौजूदा थोक समझौतों का विस्तार और भविष्य में सभी इच्छुक खिलाड़ियों को थोक 4 जी सेवाएं प्रदान करना।

° अपने ग्राहकों को एक MNO से दूसरे में स्विच करने के लिए अपने थोक भागीदारों की क्षमता में सुधार करना (यानी यदि वे चाहते हैं तो अपने MVNOs को दूसरे TSP के नेटवर्क पर स्विच करना आसान बनाना)

° http://euroDa.eu/rapid/Dress-release MEiVIO-14-460 en.doc

इसलिए, प्रस्तुत किया गया है कि यूरोप में उपरोक्त केस स्टडीज को विलय किए गए निकाय द्वारा क्षमता के आवंटन के शासनादेश के लिए माना जा सकता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को बनाए रखने और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भारतीय टेलीकॉम बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भारत में VNOs के लिए आईडिया-वोडाफोन विलय जैसे वर्तमान विलय के हकदार हैं।

वैश्विक मामले के अध्ययन अनुसार, विलय की गई इकाई के ऊपर वर्णित, अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता का बेहतर रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे। VNOs को अब विलय किए गए संस्थाओं के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किसी भी बाधा या चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्राहक ब्रांडों के बड़े विकल्प होने से लाभ उठाएंगे, अपने दूरसंचार ऑपरेटर का चयन करेंगे, और निरंतर सस्ती कीमतों और नवाचारी सेवा के प्रस्तावों का भी लाभ उठाएंगे। सरकार को विनियामक शुल्क और करों के माध्यम से बढ़े हुए राजस्व से लाभ होगा क्योंकि देश के दूरसंचार संसाधन विलय की गई इकाई द्वारा अधिक कुशलता से मुद्रीकृत किए जायेंगे।

भारत में वर्तमान परिदृश्य के लिए किसी भी शासनादेश के अभाव में जिसमें 3-निजी प्रतियोगी और एक सरकारी संस्था (BSNL) हैं।यह एक ऐसा तथ्य है जो 2016 में UL-VNO नीति के मुद्दे को प्रेरित करता है लेकिन कोई UL- VNO सेवाओं को शुरू करने में सक्षम नहीं था क्योंकि कोई TSP VNOs को क्षमता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा, यदि उद्योग में कार्टेलाइजेशन की संभावना अधिक से अधिक है, तो यदि नियामक और लाइसेंसकर्ता NTP2012 के अनुसार VNO नीति को आगे बढ़ाने के लिए TSP को आदेश देते हैं, तो VNO को अनिवार्य आवंटन के लिए TSP को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा सके। हम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से यह

न्याय कर सकते हैं जहां इस तरह के एक परिपक्व बाजार के बावजूद TSP को MVNOs को अनिवार्य करने के कारण पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और ग्राहक बड़े पैमाने पर इसके लाभ उठा रहे हैं।'

Best Regards
For Virtual Network Operators Association of India

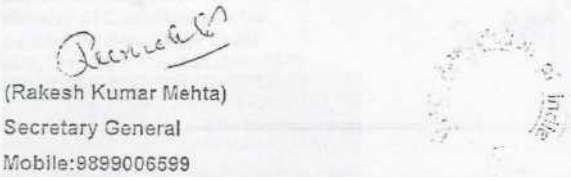

(Rakesh Kumar Mehta)
Secretary General
Mobile:9899006599

इसलिए हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के लिए ठीक प्रत्याशित और सू मोटो में संशोधन करें ताकि अंत में उपभोक्ताओं को बाजार में प्रतिस्पर्धा और नए उत्पादों की उपलब्धता की रक्षा करने के लिए विनियमों में संशोधन किया जा सके।

इ-मेल: secretary-general@vnoai.com/rk.mehta2051@gmaii.com CC-
. सचिव दूरसंचार विभाग,दूरसंचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय: वाटिका बिजनेस सेंटर, Mazzanine मंजिल, नई दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन, कनेक्टअस बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
CIN No: U64200DL20I6NPL304S74

अस्वीकरण: यह दस्तावेज मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित दस्तावेज का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह दस्तावेज मान्य होगा।